मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं नई दिल्ली से एक साथ प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र

हमारा उद्देश्य सेवा समर्पण जनकल्याण

एक सत बुलेटिन

E-mail: eksatbulletin@gmail.com | जबलपुर, बुधवार 2 सितंबर 2026 | वर्ष-07, अंक-305, पृष्ठ-08, मूल्य- दो रुपए | Website: www.eksatbulletin.in

नेपाल में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा हुआ एक हजार के पार, 3,916 लोग अब भी लापता

काठमांडू। नेपाल में बुधवार को अचानक आई बाढ़ की आपदा में मरने वालों की संख्या 1,000 के आंकड़े को पार कर गई है, जबकि चीन में भी कई लोगों की जानें गईं है और सैकड़ों लोग लापता हैं। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, देश में बाढ़ के कारण कम से कम 1,003 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 3,916 लोग अब भी लापता हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के अनुसार बाढ़ आपदा के बाद से अब तक 11,379 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है।

नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार, लापता लोगों में 583 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। राहत कार्यों के दौरान हालांकि भारत, चीन, जर्मनी, बुल्गारिया, तुर्की, इटली, अमेरिका, माल्टा, स्विट्जरलैंड, रूस, पुर्तगाल और ओमान सहित विभिन्न देशों के 315 विदेशी नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। वहीं, स्पेन, बेल्जियम और अमेरिका के पांच अन्य विदेशी नागरिक स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। चीन में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। चीन के सरकारी बयान में कहा गया है कि बाढ़ के कारण कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है और 546 से अधिक लोग लापता हैं।

चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी ने चीन के जल संसाधन मंत्रालय का हवाला देते हुए बताया है कि हिमालयी इलाके में आयी भीषण और जानलेवा बाढ़ के कुछ दिनों बाद भी, नेपाल में टकराव से बने गड्ढे के आस-पास मौजूद ग्लेशियर ह्यगिर सकते हैं, जिससे बड़ा खतरा हो सकता है।

मुख्यमंत्री डॉ.यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिये गए निर्णय

विकास और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 41 हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति

एक सत बुलेटिन, भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लगभग 41 हजार करोड़ रुपये से अधिक के महत्वपूर्ण वित्तीय प्रस्तावों और जनकल्याणकारी निर्णयों को स्वीकृति प्रदान की। राज्य में ग्रामीण विकास के ढांचे को गति देने के लिए 'विकसित भारतः वीबी जी राम जी योजना' के क्रियान्वयन के लिये 29 हजार 619 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया गया। इसके साथ ही प्रदेश की सड़क कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए पश्चिम भोपाल बायपास 4-लेन निर्माण के लिए 3 हजार 774 करोड़ रुपये और मेहलुआ-बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग के लिए 3 हजार 272 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है, जिससे राज्य में औद्योगिक और सभी तरह के आवागमन को नई ऊर्जा मिलेगी।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय संतुलन और गुणवत्ता विस्तार की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) का पुनर्गठन कर भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में तीन नए प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य के दुग्ध उत्पादकों के आर्थिक सशक्तिकरण और 'सांची' ब्रांड के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के सहयोग से 2 हजार 973 करोड़ रुपये की डेयरी विकास योजना को मंजूरी दी गई। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से चिकित्सा उपकरणों और विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 1,400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए पंजीकृत कृषकों से ग्रीष्मकालीन मूंग की उपज के उपार्जन सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया। साथ ही नवगठित जिलों मैहर, मऊगंज, पांढुर्णा और निवाड़ी में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए सामाजिक न्याय और आयुष विभागों में नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

निर्णय अनुसार नई योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अब 100 दिन के स्थान पर 125 दिनों के श्रमजन्य रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। रोजगार के दिनों में की गई यह वृद्धि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी। नई योजना का मुख्य आधार 'विकसित भारत @2047' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण बुनियादी ढांचे को तैयार करना है। अब प्रत्येक ग्राम पंचायत जी आई एस आधारित तकनीक, 'पीएम गति शक्ति' लेयर्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके 'विकसित ग्राम पंचायत योजना' तैयार करेगी। इन योजनाओं को डिजिटल पोर्टल के माध्यम से 'विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक' में समेकित किया जाएगा। योजना अंतर्गत जल सुरक्षा, जलवायु-अनुकूल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस और अत्याधुनिक आजीविका मॉडल जैसे तकनीकी कार्यों के प्रभावी संपादन के लिए मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद में एक समर्पित राज्य-स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित की जाएगी।

भारत सरकार के दिशा-निदेर्शों के अनुरूप राज्य में प्राप्त होने वाले वित्तीय आवंटन को पारदर्शी और आवश्यकता-आधारित बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को विकास मानदंडों के आधार पर क, ख, ग श्रेणियों में वगीर्कृत किया जाएगा। योजना में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति, डिजिटल मस्टर रोल और प्रत्येक छह माह में सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य किया गया है। साथ ही त्वरित शिकायत निवारण के लिए प्रत्येक जिले में एक 'लोकपाल' की नियुक्ति की जाएगी, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायतों का निराकरण करेंगे।

वीबी जी राम जी योजना के लिए 29 हजार 619 करोड़ रुपए का अनुसमर्थन

मंत्रि-परिषद ने रविकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (ग्रामीण) : वीबी जी राम जी योजना मध्यप्रदेश और इसके 1 जुलाई 2026 से प्रभावशील किए जाने का अनुसमर्थन किया। योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-2027 में अनुमानित लागत रुपये 3,183 करोड़ रुपए तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक योजना की निरंतरता के लिए कुल अनुमानित लागत 26,436 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया गया। केंद्र और राज्य का अंश 60:40 के अनुपात में होगा, जिसमें राज्यांश 10 हजार 574 करोड़ रुपए होगा। इन पाँच वर्षों में प्रशासनिक व्यय के लिए 946 करोड़ रुपए का व्यय होगा, जो राज्य शासन वहन करेगा।

X पर एडिटेड फोटो शेयर की पाकिस्तान ने SCO समिट की तस्वीर से पीएम मोदी व ईरानी राष्ट्रपति को हटाया

एजेन्सी, बिश्केक

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालयकी ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की गई एक ग्रुप फोटो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, SCO समिट के दौरान ली गई ग्रुप फोटो को एडिट करके प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटा दी गई है।

यह तस्वीर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में ली गई थी। इसमें सदस्य देशों के नेता एक मंच पर खड़े नजर आ रहे हैं। मूल तस्वीर में मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत 12 नेता दिखाई दे रहे हैं। वहीं, एडिटेड तस्वीर में सिर्फ 6 नेता दिख रहे हैं। मोदी, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजशकियान समेत 6 नेताओं को हटा दिया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी रउड समिट का ग्रुप फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें शहबाज शरीफ नजर आ रहे हैं।

6 घंटे बाद पीएमओ ने फोटो शेयर की, मोदी दिखे

इस विवाद के 6 घंटे बाद पाकिस्तान पीएमओ ने एक्स पर एससीओ की फोटो शेयर की है। इसमें पीएम मोदी भी नजर आ रहे हैं।

वैश्विक संकट में भारत की GDP 7.8% दर से बढ़ी मोदी की फिर अपील-जरूरत न हो तो सोना नहीं खरीदें

एजेन्सी, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% रहने पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि यह उपलब्धि देशवासियों की इच्छाशक्ति, मेहनत और सामूहिक ताकत का नतीजा है। पीएम मोदी ने एक बार फिर लोगों से गैर-जरूरी सोने की खरीदारी से बचने की अपील की। उन्होंने कहा, अगर जरूरत न हो तो सोना नहीं खरीदना चाहिए। इससे पहले 10 मई को भी ढट ने देशवासियों से सोना नहीं खरीदने की अपील की थी।

कुछ लोग 'झूठ की गूंज' से माहौल खराब कर रहे

पीएम मोदी ने राहुल का नाम लिए बिना कहा- देश के अंदर कुछ लोग निराशा फैलाने और 'झूठ की गूंज' के सहारे माहौल खराब

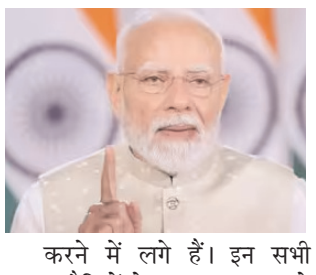

करने में लगे हैं। इन सभी चुनौतियों के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। देश को यही रफ्तार बनाए रखनी होगी और आगे भी तेजी से विकास करना होगा। उन्होंने कहा, विदेश में घूमने के लिए यात्राएं करने और विदेश में शादी करने से बचना चाहिए। लोगों को मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पीएम ने यह भी कहा, जितना ज्यादा स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाएगा, भारत उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब देश की युवा पीढ़ी को एक विकसित भारत सौंपा जाएगा।

दरअसल, राहुल लगातार छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। राहुल ने अब तक कोटा, देहरादून, प्रयागराज और पुणे में 4 कार्यक्रम किए हैं। इसमें उन्होंने पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी, महंगी शिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को उठाए।

भारत अपने इस्तेमाल का करीब 99% सोना विदेशों से खरीदता है। 2025-26 में सोने का ये इम्पोर्ट बिल करीब 6.4 लाख करोड़ रुपए का था। भारत को विदेश से सोना खरीदने पर विदेशी मुद्रा डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। जब हम सोना कम खरीदते हैं, तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहता है और डॉलर की मांग कम हो जाती है। डॉलर की मांग घटने से विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए पर दबाव कम होता है, जिससे रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत बना रहता है।

परिसर में सेल्फी और रील पर पाबंदी तमिलनाडु के 52 मंदिरों में स्मार्टफोन बैन

एजेन्सी, नई दिल्ली

तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 52 प्रमुख मंदिरों में स्मार्टफोन ले जाने और इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। यह नियम मंगलवार से लागू हुआ है। नए नियम के मुताबिक, श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश से पहले स्मार्टफोन काउंटर पर जमा करना होगा।

इसके लिए हर फोन पर 5 रुपए चार्ज देना होगा। बिना कैमरे वाले मोबाइल फोन मंदिर के अंदर ले जाने की अनुमति होगी। हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स मंत्री रमेश ने यह जानकारी दी। यह फैसला 2 दिसंबर 2022 को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के आदेश के आधार पर जारी किए गए हैं। मंदिर परिसरों में श्रद्धालुओं, खासकर युवाओं द्वारा फोटो खींचने, रील बनाने और वीडियो रिकॉर्ड करने को लेकर लगातार

चिंताएं जताई जा रही थीं।

मंत्री ने कहा कि जिन मोबाइल फोन में कैमरा नहीं है, उन्हें मंदिर के अंदर ले जाने की अनुमति होगी। नए नियम का उद्देश्य मंदिरों की पवित्रता और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना है।

कांचीपुरम के प्रसिद्ध देवराजस्वामी-अथि वरदार मंदिर में मंगलवार सुबह 6 बजे से यह व्यवस्था शुरू कर दी गई। यहां फोन जमा करने के लिए दो कंप्यूटर ऑपरेटर और दो कर्मचारी तैनात किए गए हैं।

50-सीटर प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास सहित स्वास्थ्य केन्द्र, विद्युत उपकेन्द्र और उपतहसील का केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया लोकार्पण

शिवपुरी को 17.50 करोड़ से अधिक की विकास सौगातें, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और सड़क सुविधाओं को मिली नई गति

एक सत बुलेटिन, शिवपुरी

केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शिवपुरी प्रवास के दौरान क्षेत्र को 17.50 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने अनुसूचित जाति के 50-सीटर प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास, तानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंहनिवास विद्युत उपकेन्द्र और थर्रा उपतहसील का लोकार्पण किया। साथ ही नगर पालिका की विभिन्न सड़कों तथा सिंहनिवास में सरकारी मिडिल स्कूल भवन के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया।

केन्द्रीय मंत्री ने 4.99 करोड़ की लागत से निर्मित अनुसूचित जाति के 50-सीटर प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर मानते थे कि शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम है। इसी भावना के साथ यह छात्रावास बच्चों को बेहतर शिक्षा, सुविधाओं और व्यक्तित्व

विकास का वातावरण उपलब्ध कराएगा, जिससे वे अपने सपनों को नई उड़ान दे सकेंगे।

इसके बाद केन्द्रीय मंत्री ने तानपुर में 2.95 करोड़ की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सिंहनिवास में 2.77 करोड़ की लागत से निर्मित विद्युत उपकेन्द्र का लोकार्पण किया। सिंधिया ने विश्वास व्यक्त किया कि इन परियोजनाओं से क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तथा अधिक सुदृढ़ और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति का लाभ मिलेगा।केन्द्रीय मंत्री ने नगर पालिका की विभिन्न सड़कों के 5 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। इसके साथ ही सिंहनिवास में 51 लाख की लागत से बनने वाले सरकारी मिडिल स्कूल भवन तथा ठर्रा में 1.24 करोड़ की लागत से निर्मित उपतहसील का लोकार्पण किया। उपतहसील के प्रारंभ होने से क्षेत्रवासियों को राजस्व एवं अन्य प्रशासनिक सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी। सिंधिया ने कहा कि शिवपुरी में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और प्रशासनिक सुविधाओं तक विकास का लाभ हर परिवार तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में शिवपुरी सहित पूरे क्षेत्र में विकास कार्यों को निरंतर गति दी जा रही है।

केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने हरी झंडी दिखाकर कोलारस स्टेशन पर उज्जैनी एक्सप्रेस के प्रायोगिक ठहराव का किया शुभारंभ

भोपाल। कोलारस एवं आसपास के क्षेत्र के रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सौगात के रूप में उज्जैनी एक्सप्रेस का कोलारस रेलवे स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव प्रारंभ हो गया है। माननीय केंद्रीय संचार एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री, भारत सरकार श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कोलारस रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाकर उज्जैनी एक्सप्रेस के प्रायोगिक ठहराव का शुभारंभ किया। यात्रियों की सुविधा एवं क्षेत्रीय रेल संपर्क को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गाड़ी संख्या 14309/14310 लक्ष्मीबाई नगरझयोगनगरी ऋषिकेशझलक्ष्मीबाई नगर उज्जैनी एक्सप्रेस का भोपाल मंडल के कोलारस स्टेशन पर दो मिनट का ठहराव प्रदान किया गया है। गाड़ी संख्या 14310 योगनगरी ऋषिकेशझलक्ष्मीबाई नगर उज्जैनी एक्सप्रेस का कोलारस स्टेशन पर आगमन 20:43 बजे एवं प्रस्थान 20:45 बजे रहेगा। यह ठहराव 01 सितंबर 2026 से प्रभावी है। वहीं गाड़ी संख्या 14309 लक्ष्मीबाई नगरझयोगनगरी ऋषिकेश उज्जैनी एक्सप्रेस का कोलारस स्टेशन पर आगमन 23:34 बजे एवं प्रस्थान 23:36 बजे रहेगा। इसका ठहराव 02 सितंबर 2026 से प्रभावी होगा।

'मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान' के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में 'संपर्क अभियान 2026' को मिली बड़ी सफलता

4838 शिविरों में 2 लाख 15 हजार 035 शिकायतों का मौके पर निराकरण

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का उनके घर के नजदीक त्वरित समाधान उपलब्ध कराने तथा मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संचालित 'संपर्क अभियान 2026' को उल्लेखनीय सफलता मिली है। 14 मई से प्रारंभ हुए इस विशेष अभियान के अंतर्गत भोपाल एवं ग्वालियर रीजन के 16 जिलों में अब तक 4,838 विशेष शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 2 लाख 15 हजार 035 उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर ही त्वरित निराकरण किया गया। अभियान के माध्यम से उपभोक्ताओं को स्थानीय स्तर पर सुविधाजनक एवं त्वरित समाधान उपलब्ध कराते हुए विद्युत सेवाओं में पारदर्शिता, सुगमता और उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़ावा दिया जा रहा है।

भोपाल रीजन के वृत्तों में लगे शिविर

भोपाल रीजन के अंतर्गत शहर वृत्त भोपाल में 359 शिविरों में 21,569 शिकायतों का निराकरण किया गया। बैतूल (ओ एंड एम) वृत्त में 427 शिविरों में 24,684 शिकायतों का निराकरण, भोपाल (ओ एंड एम) वृत्त में 246 शिविरों में 9,593 शिकायतों का निराकरण, हरदा वृत्त में 127 शिविरों में 17,477 शिकायतों का

निराकरण, नर्मदापुरम वृत्त में 326 शिविरों में 26,368 शिकायतों का निराकरण, रायसेन वृत्त में 244 शिविरों में 16,378 शिकायतों का निराकरण, राजगढ़ वृत्त में 351 शिविरों में 4,798 शिकायतों का निराकरण, सीहोर वृत्त में 312 शिविरों में 7,106 शिकायतों का निराकरण तथा विदिशा वृत्त में 204 शिविरों में 10,940 शिकायतों का निराकरण किया गया। ग्वालियर रीजन के अंतर्गत शहर वृत्त ग्वालियर में 287 शिविरों में 5,844 शिकायतों का निराकरण किया गया। वहीं अशोकनगर वृत्त में 143 शिविरों में 15,781, भिंड (ओ एंड एम) वृत्त में 274 शिविरों में 5,625, दतिया (ओ एंड एम) वृत्त में 169 शिविरों में 7,430, गुना वृत्त में 247 शिविरों में 9,138, ग्वालियर (ओ एंड एम) वृत्त में 239 शिविरों में 4,316, मुरैना वृत्त में 377 शिविरों में 15,757, श्योपुर (ओ एंड एम) वृत्त में 182 शिविरों में 5,046 तथा शिवपुरी वृत्त में 324 शिविरों में 7,185 शिकायतों का निराकरण किया गया। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायतों का ऑन-द-स्पॉट समाधान करना है। शिविरों में मुख्य रूप से त्रुटिपूर्ण बिल, मीटर रीडिंग एवं अन्य बिलिंग संबंधी शिकायतों का तत्काल निराकरण किया गया। साथ ही मात्र 5 रुपये में नवीन ग्रामीण घरेलू एवं कृषि पंप कनेक्शन प्रदान किए गए। इसके अलावा भार वृद्धि, नाम परिवर्तन, श्रेणी परिवर्तन, स्थायी कनेक्शन विच्छेदन, अस्थायी कनेक्शन, ई-केवाईसी, अनापत्ति प्रमाण-पत्र , बंद/खराब मीटर बदलना, स्मार्ट मीटर संबंधी शिकायतों का निराकरण, सर्विस केबल सुधार, वोल्टेज संबंधी समस्याओं का समाधान, ट्रांसफार्मर से जुड़ी शिकायतों का निराकरण, बिजली बिलों का आंशिक एवं पूर्ण भुगतान, अग्रिम भुगतान पर छूट, बकाया राशि जमा कराने सहित विभिन्न जनहितैषी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ प्रदान किए गए।

12 सितंबर को तृतीय नेशनल लोक अदालत का होगा आयोजन

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहनों को किया रवाना

12 सितंबर को भोपाल में वर्ष 2026 की तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को त्वरित, सुलभ और सर्वमान्य न्याय दिलाना है। इस लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव ने भोपाल जिला न्यायालय परिसर से विशेष प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन जिंगल्स और फ्लेक्स बैनरों के माध्यम से जिले के शहरी व ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को लोक अदालत के फायदों के प्रति जागरूक करेंगे।

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के दिशा-निर्देशों तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में आगामी 12 सितंबर 2026 को

आयोजित होने वाली वर्ष 2026 की तृतीय नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार का विधिवत शुभारंभ किया गया। इसी श्रृंखला में जिला न्यायालय परिसर भोपाल से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये प्रचार वाहन जिंगल्स और भव्य फ्लेक्स बैनरों के माध्यम से भोपाल जिले के शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ सुदूर ग्रामीण अंचलों में नागरिकों को लोक अदालत के माध्यम से सुलभ न्याय प्राप्त करने के लिए जागरूक करेंगे।लोक अदालत के बहुआयामी एवं जनहितकारी स्वरूप को रेखांकित करते हुए बताया गया कि यह मंच पक्षकारों के मध्य कटुता को समाप्त कर पारस्परिक सौहार्द एवं सद्भाव को पुनर्स्थापित करने का एक सशक्त जरिया है। इसके माध्यम से प्रकरणों के त्वरित समाधान से पक्षकारों के अमूल्य समय, धन एवं श्रम की बचत होती है। लोक अदालत की सबसे अनूठी विशेषता यह है कि इसमें किसी पक्ष की पराजय नहीं होती, बल्कि दोनों ही पक्षों की जीत सुनिश्चित होती है। प्रकरण का निराकरण होने पर न्याय शुल्क की शत-प्रतिशत वापसी संभव होती है तथा लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होता है, जिसके विरुद्ध किसी अपील का प्रावधान न होने से वर्षों पुराना विवाद सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। इस अवसर पर न्यायपालिका, जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश श्री राजर्षि श्रीवास्तव, जिला न्यायाधीश श्री दीपक बंसल, जिला न्यायाधीश श्री संजय कुमार शाही, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अग्नीन्ध्र कुमार द्विवेदी, सचिव एवं न्यायाधीश (जिविसेप्रा) श्री सुनीत अग्रवाल, विभिन्न जिला न्यायाधीशगण एवं न्यायिक मजिस्ट्रेटगण उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त डिप्टी कलेक्टर श्री रत्नेश श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री विशाल शाहवाल, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मुहम्मद जीलानी, जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र रावत, सचिव श्री मुकेश नागपुरे तथा पुलिस, प्रशासन, विद्युत विभाग एवं नगर निगम के अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में अधिकारियों ने सुनी आवेदकों की समस्याएं, सुनवाई में 131 आवेदन प्राप्त

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में एडीएम श्री सुमित पांडेय, श्री पीसी शाक्य, श्री प्रकाश नायक ने मंगलवार को जिले से जनसुनवाई में आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान अनेक समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया गया। जनसुनवाई में आए नागरिकों से 131 आवेदन प्राप्त हुए।

इस मौके पर एसडीएम एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। एडीएम श्री पांडेय, श्री शाक्य, श्री नायक ने जनसुनवाई में आए हर एक आवेदक से धैर्यपूर्वक उनकी समस्याओं पर चर्चा की और उन्हें उनके शीघ्र निराकरण का आश्वासन भी दिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को नागरिकों से प्राप्त आवेदनों पर संवेदनशील रूख अपनाते हुए निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवेदकों की समस्याओं पर संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

नरेश महाराज के सानिध्य में भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का हुआ शुभारंभ

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

प्रगति नगर में मंगलवार से नरेश महाराज के सानिध्य में सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। कथा संयोजक श्री मोनू महाराज ने बताया कि कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर धार्मिक भजनों और जयकारों के बीच यात्रा में सहभागिता की। कलश यात्रा के दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण के जयकारे लगाए और मार्ग में पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। कथावाचक नरेश महाराज ने भागवत महापुराण के महत्व पर प्रकाश

डालते हुए कहा कि श्रीमद्भागवत कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन को संस्कार, भक्ति और सद्मार्ग की ओर ले जाने का माध्यम है। उन्होंने श्रद्धालुओं से कथा श्रवण के साथ उसके संदेश को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। आयोजकों ने बताया कि कथा सात दिनों तक चलेगी, जिसमें प्रतिदिन भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं, भक्ति, धर्म और जीवन मूल्यों से जुड़े प्रसंगों का संगीतमय वर्णन किया जाएगा। आयोजन में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। कथा के शुभारंभ अवसर पर प्रगति नगर सहित आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालु और आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

कोलार परियोजना से जुड़े क्षेत्रों में आज जलप्रदाय प्रभावित रहेगा

भोपाल। नगर निगम भोपाल की कोलार जलप्रदाय परियोजना के शुद्ध जल पंपगृह में बटरफ्लाई वाल्व बदलने और विद्युत सबस्टेशन में आवश्यक संधारण कार्य के चलते बुधवार, 2 सितंबर को संबंधित क्षेत्रों में जलप्रदाय प्रभावित रहेगा। नगर निगम के अनुसार पंपगृह एवं विद्युत सबस्टेशन में संधारण कार्य सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। इसके कारण बरखेड़ी कला, डीआरपी लाइन, नया बसेरा, एजी कॉलोनी, राजीव नगर बस्ती, शिवाजी नगर, तुलसी नगर, ई-6 एवं ई-7 अरेरा कॉलोनी, जनता क्वार्टर, बैंक कॉलोनी, निशातपुरा, हमीदिया रोड, छावनी, पटेल नगर, इब्राहिमगंज, कबाड़खाना, शास्त्री नगर, न्यू एवं ओल्ड 228 क्वार्टर, न्यू एमएलए क्वार्टर सहित अनेक क्षेत्रों में जलप्रदाय प्रभावित रहेगा।

दानापुर से सर एम विश्वेश्वरय्या टर्मिनल बेंगलुरु के मध्य प्रतिदिन स्पेशल ट्रेन अब नियमित नए नंबर से संचालन

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

रेल मंत्रालय द्वारा यात्रियों को सुगम, संरक्षित एवं आरामदायक यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे पर चल रही स्पेशल ट्रेनों को नए नम्बरों के साथ नियमित चलाने का निर्णय लिया जा रहा है। इसी कड़ी में स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 03251/03252 दानापुर-सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल बेंगलुरु-दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन को नियमित करते हुए रेगुलर नए नम्बर से संचालित करने का निर्णय रेल प्रशासन द्वारा लिया गया है। अब यह ट्रेन नियमित नए नम्बर 22365/22366 के रूप में प्रतिदिन संचालित होगी। यह ट्रेन पश्चिम मध्य रेल के सतना, जबलपुर एवं इटारसी स्टेशनों से होकर गुजरेगी। 22365 दानापुर-सर एम. विश्वेश्वरय्या

टर्मिनल बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन समय सारिणीः- गाड़ी संख्या 22365 दानापुर-सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन प्रतिदिन दिनाँक 01 सितम्बर 2026 से दानापुर से दोपहर 14:45 बजे प्रस्थान कर, मार्ग से होते हुए सतना मध्यरात्रि 00:10 बजे, जबलपुर 03:25 बजे, इटारसी 07:20 बजे पहुँचकर निर्धारित मध्यवर्ती स्टेशनों से होते हुए तीसरे दिन दोपहर 14:30 बजे सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल बेंगलुरु पहुँचेगी। 22366 सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल बेंगलुरु-दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन समय सारिणीः- गाड़ी संख्या 22366 सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल बेंगलुरु-दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन दिनाँक 03 सितम्बर 2026 से सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल बेंगलुरु से रात्रि 23:50 बजे प्रस्थान कर, निर्धारित मध्यवर्ती स्टेशनों से होते हुए इटारसी 05:50 बजे, जबलपुर 09:00 बजे, सतना 13:00 बजे पहुँचकर और चौथे दिन मध्यरात्रि 00:15 बजे दानापुर पहुँचेगी। ठहराव स्टेशनः- यह ट्रेन दोनों दिशाओं में आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रायगराज छिवकी, सतना, जबलपुर, इटारसी जंक्शन, नागपुर जंक्शन, सेवाग्राम, चन्द्रपुर, ओंगोल, गुडुर जंक्शन, पेरम्बूर, काटपाडी जंक्शन, जोलारपेट्टई जंक्शन, बांगरपेट जंक्शन एवं व्हाइट फील्ड स्टेशनों पर रुकेगी।

एनएचएआई की निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं की ने की विस्तृत समीक्षा

शहपुरा (भिटौनी) टोल पर अस्थायी रूप से बंद होगा टोल संग्रह : मंत्री राकेश सिंह

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने मंगलवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा प्रदेश में किए जा रहे निर्माण कार्यों तथा भविष्य के लिए प्रस्तावित वृहद सड़क परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में एनएचएआई के अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से वर्तमान में प्रगतिरत परियोजनाओं की स्थिति तथा प्रस्तावित नई परियोजनाओं की कार्ययोजना की जानकारी दी। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव, सड़क सुरक्षा, निर्माण गुणवत्ता तथा वर्षाकाल के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री श्री सिंह ने भोपाल-इंदौर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तथा उज्जैन-झालावाड़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से संबंधित आवश्यक प्रक्रियाओं को शीघ्र पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण इन वृहद सड़क परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। संबंधित स्तरों पर सभी आवश्यक कार्रवाई तेजी से पूरी की जाए। जबलपुर रिंग रोड के चार पैकेज दिसंबर 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश मंत्री श्री सिंह ने बैठक में जबलपुर रिंग रोड के निर्माण कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की गई। रिंग रोड का निर्माण कुल पाँच पैकेजों में किया जा रहा है। इनमें चार पैकेजों में कार्य की प्रगति संतोषजनक पाई गई, जबकि पाँचवें

पैकेज में अपेक्षित गति से कार्य नहीं होने पर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंत्री श्री सिंह ने चार पैकेजों का कार्य दिसंबर 2026 तक तथा पाँचवें पैकेज का कार्य जून 2027 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए, जिससे संपूर्ण जबलपुर रिंग रोड का निर्माण निर्धारित समय-सीमा में पूरा हो सके। शहपुरा (भिटौनी) टोल पर अस्थायी रूप से बंद होगा टोल संग्रह भोपाल-जबलपुर मार्ग पर शाहपुर रेलवे ब्रिज के क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात को डायवर्ट किया जा रहा है। इसके चलते शहपुरा स्थित टोल पर लिए जा रहे टोल को लेकर स्थानीय समुदाय में असंतोष की स्थिति बनी हुई है। मंत्री श्री सिंह ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए शहपुरा (भिटौनी) टोल नाके पर अस्थायी रूप से टोल संग्रह बंद करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और गुणवत्ता पर विशेष जोर एनएचएआई के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि प्राधिकरण के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग किसी न किसी अनुबंध के अंतर्गत संधारित किए जा रहे हैं। जिन सड़कों की परफॉर्मेंस गारंटी अवधि समाप्त हो चुकी है अथवा जिनके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, उनके रखरखाव के लिए शॉर्ट टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट तथा लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से मरम्मत एवं संधारण कार्य कराया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि वर्षाकाल के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। मंत्री श्री सिंह ने निर्देश दिए कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव के स्तर को बेहतर बनाया जाए तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत में किसी भी प्रकार की देरी नहीं हो। उन्होंने नई प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं से संबंधित प्रक्रियाओं को भी गति देने के निर्देश दिए। जबलपुर-दमोह मार्ग की शीघ्र मरम्मत के निर्देश मंत्री श्री सिंह ने जबलपुर-दमोह मार्ग पर आवश्यक मरम्मत कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने के निर्देश दिए।

दुकानदार तैयार, दुकानें तैयार... फिर भी नहीं खुल रहे ताले

करोड़ों की लागत से बने गुरंदी मछली मार्केट का उद्घाटन, लटके ताले खोल रहे बदहाली की पोल

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

शहर के पुराने और व्यस्त बाजारों में शुमार गुरंदी मछली मार्केट इन दिनों नगर निगम की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। दुकानदारों को बेहतर और व्यवस्थित बाजार देने के उद्देश्य से बनाया गया नव निर्मित मछली मार्केट उद्घाटन के बाद भी ताले में बंद है। मार्केट की सफाई हो चुकी है, बोर्ड भी लग चुका है और नगर निगम आयुक्त एवं कलेक्टर तक इसका निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद दुकानदारों को दुकानें सौंपने और मार्केट शुरू करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मार्केट तैयार हो गया, उद्घाटन हो गया, सफाई हो गई, निरीक्षण हो गया और पहचान के लिए बोर्ड तक लग गया, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसके दरवाजों पर ताला जड़ दिया गया? मार्केट से जुड़े दुकानदार और स्थानीय लोग भी असमंजस में हैं। किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं है कि मार्केट का संचालन कब शुरू होगा और दुकानों का आवंटन अथवा हस्तांतरण कब किया जाएगा। लंबे समय से नई व्यवस्था की उम्मीद लगाए बैठे दुकानदार अब सिर्फ ताले को देखते रह गए हैं।एक ओर दुकानदार अपनी रोजी-रोटी के लिए व्यवस्थित स्थान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नगर निगम की तैयार संपत्ति उपयोग में आने के बजाय बंद पड़ी है। जिस संपत्ति पर जनता का पैसा लगा है, उसका इस तरह लंबे समय तक बंद रहना अपने आप में गंभीर सवाल है। मार्केट तैयार है, लेकिन व्यवस्था गायब है। यदि किसी तकनीकी, प्रशासनिक या आवंटन संबंधी कारण से मार्केट शुरू नहीं हो पा रहा है तो नगर निगम को इसकी स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए।स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारी निरीक्षण करने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन निरीक्षण के बाद क्या कार्रवाई हुई और मार्केट कब शुरू होगा, इसकी जानकारी देने वाला कोई नहीं है। स्मार्ट सिटी के दावों के बीच गुरंदी की तस्वीर जबलपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही जाती है, लेकिन गुरंदी बाजार की तस्वीर इन दावों से बिल्कुल अलग नजर आती है। बाजार क्षेत्र में गंदगी, अव्यवस्था और बंद पड़ी सरकारी संपत्ति व्यवस्था की पोल खोलती दिखाई दे रही है। सवाल यह भी है कि जब शहर को व्यवस्थित और आधुनिक बनाने की कवायद चल रही है, तब गुरंदी जैसे पुराने और महत्वपूर्ण बाजार की सुध लेने में जिम्मेदार विभाग आखिर क्यों पीछे है? स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों की मांग है कि नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी एक बार फिर मौके का निरीक्षण कर मार्केट बंद होने की वास्तविक वजह स्पष्ट करें और जल्द से जल्द ताला खुलवाकर दुकानों का संचालन शुरू कराएं।सिस्टम की लापरवाही से शोपीस बना बाजार मछली विक्रेताओं को एक व्यवस्थित और स्वच्छ वातावरण देने के उद्देश्य से इस अत्याधुनिक मार्केट का निर्माण कराया गया था। इसमें पानी की निकासी, साफ-सफाई और वेंडिंग जोन की आधुनिक सुविधाएं प्रस्तावित थीं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि नेताओं और अधिकारियों ने उद्घाटन करके सुर्खियां तो बटोर लीं, लेकिन इसके संचालन की जमीनी व्यवस्था करना भूल गए। सड़क पर कारोबारः नया मार्केट बंद होने के कारण विक्रेता पुराने ढर्रे पर ही मुख्य मार्ग पर दुकानें सजा रहे हैं, जिससे आए दिन जाम और दुर्गंध की स्थिति बनी रहती है। लागत पर उठे सवालः जनता और स्थानीय व्यापारियों का सवाल है कि जब मार्केट को चालू ही नहीं करना था, तो जनता के पैसों से बनी इस बहुमंजिला संरचना का जल्दबाजी में उद्घाटन क्यों किया गया? सुरक्षा और रख-रखाव पर खतराः लंबे समय से बंद पड़े होने के कारण अब नए परिसर में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने लगा है और रखरखाव के अभाव में ढंचा खराब हो रहा है।

संभागायुक्त ने की विभागवार कार्यों की समीक्षा, वर्षा जनित संक्रामक रोगों की रोकथाम के निर्देश

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

संभागायुक्त धनंजय सिंह ने संभागीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक की, जिसमें शासन के प्रमुख कार्यक्रमों और प्राथमिक अभियानों की प्रगति की विस्तृत चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में संभागायुक्त सिंह ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि लंबित शिकायतों का त्वरित रूप से संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान अंतर्गत लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा के दौरान सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का समय सीमा में प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित करायें। साथ ही अभियान अंतर्गत लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने हेतु संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। संभागायुक्त ने स्वास्थ्य व पोषण से जुड़े विषयों को प्राथमिकता में लेते हुए कहा कि इस दिशा में अपेक्षित मापदंड अनुसार कार्य करें। उन्होंने दस्तक अभियान अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग तथा महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों से प्रगति का जायज़ा लेकर समय सीमा में इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिए। संभागायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को वर्षा जनित संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं उपचार हेतु तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया।

संयुक्त संचालक गिरीश मेश्राम ने किया मत्स्यबीज प्रक्षेत्र का निरीक्षण

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

मत्स्य विभाग के संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग गिरीश मेश्राम ने मंगलवार को मत्स्यबीज प्रक्षेत्र गोकलपुर का भ्रमण एवं निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रक्षेत्र में चल रहे मत्स्यबीज उत्पादन व संवर्धन कार्यों का अवलोकन करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान संयुक्त संचालक श्री मेश्राम ने प्रजनक तालाबों का अवलोकन करते हुए मत्स्यबीज उत्पादन, नर्सरी प्रबंधन, जल गुणवत्ता और मत्स्यबीज की गुणवत्ता की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण मत्स्यबीज के उत्पादन और बेहतर प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। संयुक्त संचालक श्री मेश्राम ने प्रक्षेत्र की व्यवस्थाओं को सुधारने, संसाधनों का भरपूर उपयोग करने और जिले के मत्स्य पालकों को समय पर उच्च गुणवत्ता का मत्स्यबीज उपलब्ध कराने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

निगम आयुक्त का कड़ा रुख, राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से निगमायुक्त ने राजस्व वसूली अभियान में तेजी लाने के संबंध में आज एक बैठक आयोजित की। निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने राजस्व संग्रह को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि प्रतिदिन टैक्स वसूली करना टैक्स कलेक्टर की प्राथमिक जिम्मेदारी है। बैठक में उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाले तीन कर्मचारियों का एक-एक वेतन वृद्धि रोकने के साथ ही उनका स्थानांतरण करने के आदेश दिए हैं। निगमायुक्त द्वारा ?100 प्रतिशत वसूली के लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए संभागीय अधिकारियों, राजस्व निरीक्षकों, सहायक निरीक्षकों और कर संग्राहकों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि अभियान को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए शहर में संचालित कार बाजारों, मैरिज गार्डन, गाड़ी धुलाई सेंटरों, कैफेटेरिया और सड़क किनारे की व्यावसायिक दुकानों का गहन निरीक्षण किया जाएगा। बिना अनुमति या बिना लाइसेंस के चल रहे प्रतिष्ठानों पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की इस पहल से न केवल अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर लगाम लगेगी, बल्कि शहर के राजस्व में भी वृद्धि होगी जिसका सीधा लाभ जनता को बेहतर नागरिक सुविधाओं के रूप में मिलेगा। राजस्व एवं बाजार विभाग के सभी अधिकारियों को मैदान में उतरकर वसूली कार्यों को गति देने के निर्देश दिए गए हैं। इस पूरे अभियान की प्रगति का आकलन करने के लिए दो दिन बाद पुनः समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में सभी विभागीय प्रमुख आदि उपस्थित रहे।

हर जोन में बनेगा एक-एक आदर्श वार्ड

जबलपुर। शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और शहरवासियों को एक स्वच्छ परिवेश देने के लिए निगमायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा की। समीक्षा बैठक के साथ-साथ निरीक्षण के दौरान निगमायुक्त ने शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। बैठक में निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने निर्देशित किया कि यदि निरीक्षण के दौरान कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी पाई गई तो स्वच्छता मानकों में कोताही बरतने वाले लोगों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई की जाएगी। शहर में स्वच्छता के नए मानक स्थापित करने के लिए नगर निगम ने एक अभिनव योजना तैयार की है।

कांग्रेस का धरना : एक उपभोक्ता के बकाया बिल की सजा पूरे ट्रांसफार्मर को देने का आरोप

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

बिजली विभाग की कथित मनमानी और बिल वसूली के नाम पर की जा रही कार्रवाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी (शहर) ने मंगलवार को मिशन कंपाउंड स्थित अधीक्षण अभियंता (एसई) कार्यालय में धरना-प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जमकर नारेबाजी की और अपनी आपत्ति दर्ज कराई। कांग्रेस का आरोप है कि बिजली बिल की वसूली के नाम पर विभाग द्वारा ऐसा तरीका अपनाया जा रहा है, जिसमें एक ही ट्रांसफार्मर से जुड़े कुछ उपभोक्ताओं का बिल बकाया होने पर पूरे ट्रांसफार्मर की बिजली बंद कर दी जाती है। पार्टी नेताओं ने कहा कि इसका खामियाजा उन उपभोक्ताओं को भी भुगतना पड़ता है, जिन्होंने समय पर अपने बिजली बिलों का भुगतान किया है। धरने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बिल बकाया होने पर संबंधित उपभोक्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन पूरे क्षेत्र की बिजली बंद कर देना उन उपभोक्ताओं के साथ अन्याय है, जो नियमित रूप से अपने बिल जमा कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसे विभाग की मनमानी और तानाशाहीपूर्ण कार्यप्रणाली बताते हुए तत्काल रोक लगाने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई और मांग की कि सामूहिक रूप से बिजली काटने की व्यवस्था को तत्काल समाप्त किया जाए। साथ ही जिन क्षेत्रों में इस तरह बिजली बंद की गई है, वहां आपूर्ति बहाल कर उपभोक्ताओं को राहत दी जाए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने कहा कि बिजली जनता की मूलभूत जरूरत है और बिल वसूली के नाम पर ईमानदार उपभोक्ताओं को परेशान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के अधिकारों के लिए सड़क से लेकर संबंधित विभाग के कार्यालय तक अपनी आवाज उठाती रहेगी। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि बिजली विभाग ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया और सामूहिक बिजली कटौती पर रोक नहीं लगाई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिनेश यादव, नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा, पार्षद अयोध्या तिवारी, संतोष दुबे, हर्षित यादव, सतेंद्र चौबे, प्रवींद्र सिंह चौहान, रितेश गुप्ता बंटी, अनुज श्रीवास्तव, आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

ट्रेन में घायल 13 वर्षीय यात्री को स्टेशन पर मिली तत्काल चिकित्सा

जबलपुर। ट्रेन में घायल अवस्था में सफर कर रहे 13 वर्षीय यात्री को जबलपुर रेलवे स्टेशन पर तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराकर अस्पताल पहुंचाया गया। घटना मंगलवार की है। रेल मदद 139 और उप स्टेशन प्रबंधक (परिचालन) के माध्यम से सूचना मिली थी कि ट्रेन संख्या 11202 में एक यात्री घायल अवस्था में अधारताल से जबलपुर लाया जा रहा है। सूचना मिलते ही रेलवे की टीम सक्रिय हुई। अनन्या क्लिनिक के ईएमआर स्टाफ अतुल राव, ऑन-ड्यूटी टीसी स्टाफ और उप स्टेशन प्रबंधक (वाणिज्य) निखिल शुक्ला ने स्टेशन पर पहुंचकर घायल यात्री को अटेंड किया। यात्री की पहचान मोहम्मद नसरूल (13) के रूप में हुई। ईएमआर स्टाफ ने मौके पर ही यात्री को प्राथमिक उपचार दिया और आगे के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी। इसके बाद आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे अस्पताल को सूचना देकर आवश्यक समन्वय किया गया।

6 सालों से अटका रेलवे पुल नंबर 2 चौड़ीकरण कार्य, 5 करोड़ लागत बढ़ी, उपभोक्ता मंच ने नोटिस भेजा

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर।

रेलवे पुल नंबर 2 के चौड़ीकरण का काम पिछले 6 वर्षों से लटका पड़ा है, चौड़ीकरण हेतु बॉक्स गर्डरसेगमेंट भी लगाये गये हैं, लेकिन आगे का काम ठप्प पड़े रहने से यहां पर झाड़िया उग गई, पानी भर कर नुकसान हुआ है। जो कार्य कुछ ही करोड़ में पूरा होना था, उसमें देरी होने से लागत, बजट बढ़ गया, शासन पर 5 करोड़ की आर्थिक चोट पड़ी है। इस पर उच्चस्तरीय समिति गठित कर जॉच हो, तथा दोषियों पर कार्यवाही करें। यह नोटिस नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने जनरल मैनेजर (रेल्वे जोन) तथा संभागीय आयुक्त जबलपुर को भेजा है। इसकी प्रतिलिपियाँ आयुक्त नगर निगम तथा सीनियर डीसीएम रेल्वे को भी भेजी हैं। मंच ने बताया की इस रेल्वे ब्रिज की वर्तमान चौड़ाई साढ़े 5 मीटर है, चौड़ाई बढ़ने पर यहां 11 मीटर का रास्ता मिलेगा। रेल्वे ने जबलपुर शहर के ब्रिजों के चौड़ाई के काम करने के लिए 8 करोड़ का बजट नगर निगम को दिया था, उसमें से 6 वर्ष पूर्व में नगर निगम ने रेल्वे को 5 करोड़ दिये है, अब रेल्वे ब्रिज नं.4 के चौड़ाई का काम हुआ, लेकिन ब्रिज नं.2 का कार्य लटका पड़ा है। कार्य में देरी होने से रेल्वे अब 8 करोड़ की जगह 10 करोड़ मांग रहा है। स्पष्ट है की शासन को लगभग 5 करोड़ का नुकसान हुआ है। रेल्वे ब्रिज नं.2 से मंडला रोड जुड़ा हुआ है, यहां से हजारों की संख्या में नागरिक हर रोज गुजरते है। हमेशा जाम की स्थिति बन रही है। मंच की बैठक में डॉ. पी.जी. नाजपांडे, रजत भार्गव, एड. वेदप्रकाश अघौलिया, मनीष शर्मा, सुशीला कनौजिया, गीता पांडे, यशवंत कोष्ठ, अशोक यादव, श्याम सोलंकी आदि शामिल थे।

एटीएम कार्ड बदलकर खाते से उड़ाए 80 हजार

साइबर ठगों ने रिश्तेदार बनकर मूर्तिकार से 1 लाख रुपये ट्रांसफर कराए

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

साइबर ठगों ने लोगों को झांसे में लेकर बैंक खातों से रकम उड़ाने के नए-नए तरीके अपना लिए हैं। गढ़ा में एटीएम में कार्ड फंसने के बाद मदद का झांसा देकर एक अज्ञात व्यक्ति ने महिला का एटीएम कार्ड बदल लिया और पिन देखकर उसके खाते से 80 हजार रुपये निकाल लिए। वहीं घमापुर में एक मूर्तिकार को रिश्तेदार बताकर ठग ने उसके खाते में रकम आने का फर्जी मैसेज दिखाया और अलग-अलग खातों में कुल एक लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए। दोनों मामलों में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गढ़ा पुलिस के अनुसार धनवंतरीनगर निवासी सुनीता भानू त्रिपुरी चौक के पास स्थित एसबीआई के एटीएम से रुपये निकालने गई थीं। इसी दौरान उनका एटीएम कार्ड मशीन में फंस गया। उनके पीछे खड़े एक अज्ञात व्यक्ति ने मदद करने के बहाने उनसे कहा कि पिन नंबर डालने पर कार्ड बाहर निकल जाएगा। महिला ने उसकी बात पर भरोसा करते हुए एटीएम का पिन डाल दिया। आरोपी ने पिन देख लिया और इसी दौरान हाथ की सफाई दिखाते हुए चोरी-छिपे उनका एटीएम कार्ड बदल दिया। महिला को इसकी भनक तक नहीं लगी और वह घर चली गई। शाम करीब 7 बजे मोबाइल पर बैंक खाते में रकम से संबंधित मैसेज आया। मैसेज देखकर उन्हें शक हुआ और उन्हें एटीएम में मिले युवक की करतूत याद आई। इसके बाद उन्होंने एसबीआई पहुंचकर बैंक स्टेटमेंट निकलवाया, जिसमें पता चला कि उनके खाते से 80 हजार रुपये निकाले जा चुके थे। इसके बाद उन्होंने गढ़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई। दूसरा मामला घमापुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक मूर्तिकार संतोष कुमार प्रजापति के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने रिश्तेदार होने का झांसा देकर संपर्क किया। आरोपी ने अपने खाते से रकम भेजने और संतोष से वह रकम किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करने के लिए कहा। आरोपी द्वारा बताए गए मोबाइल नंबर पर बलराम लोधी नाम दिखाई दे रहा था। संतोष उसकी बातों में आ गए और अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए 30 हजार, 15 हजार, 30 हजार और 25 हजार रुपये, यानी कुल एक लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में संतोष को संदेह हुआ। उन्होंने जब पूरे मामले को समझा तो पता चला कि आरोपी ने उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए अपने मोबाइल से खाते में रकम आने संबंधी मैसेज भेजे थे और इसी झांसे में लेकर उनके खाते से रकम ट्रांसफर करा ली। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। पुलिस दोनों मामलों में आरोपियों और रकम के लेन-देन से जुड़े खातों व मोबाइल नंबरों की जांच कर रही है।

संपादकीय

सियासी आपूर्ति का दरिया

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मांग और आपूर्ति का चिट्ठा खोलते प्रश्न बताते हैं कि कुछ अनावश्यक ढांचा हमने अपना लिया है। विधायक रणधीर शर्मा के प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि डिनोटिफाई 1526 स्कूलों में 734 ऐसे स्कूल हैं, जहां एक भी छात्र नहीं था। अगर इसी तरह हर विभाग की कार्यक्षमता का हवाला सामने आए तो यकीनन कई सफेद हाथी सामने आएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में चंबा मेडिकल कालेज का जिक्र स्वयं मुख्यमंत्री ने किया है जहां फैकल्टी पूरी तरह कायम रखने के लिए आज भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। यानी मांग और आपूर्ति के जिस हिसाब से शिक्षण व मेडिकल संस्थान खुले हैं, उनकी उपयोगिता सिद्ध करने की बुनियाद पर संदेह है। क्या चंबा में मेडिकल कालेज की स्थापना से चिकित्सकीय सेवाएं मुकम्मल होंगी या आधा चंबा जिला आज भी कांगड़ा के टीएमसी में खुद को सुविधाजनक पाता है। हमने एम्स को अहम व सत्ता के प्रभाव में तोलते हुए जो स्थान चयनित किया, क्या वह उचित निर्णय था या साबित हो रहा है। राजनीति गवाह है कि किस तरह हमारी सरकारों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय से धर्मशाला की जमीन खींच ली। यहां कार्यालयों का भवन और संस्थानों को इमारतों की तरह देखते हुए क्षेत्रीय असंतुलन की एक प्रतिस्पर्धा दशकों से जारी है।

हमने शहरीकरण को इसकी मांग के आधार पर नहीं समझा, बल्कि राजनीतिक आधार पर नगर निगमों के गठन में समझा। प्रदेश की सबसे बड़ी औद्योगिक व शहरी आबादी बीबीएन में तकरीबन चार लाख है, तो क्या हम वहां की भौगोलिक, औद्योगिक, रिहायशी व नागरिक सुविधाओं की मांग को पूरा कर पाए। आश्चर्य यह कि जहां राजनीति का प्रभाव बढ़ गया, वहां शिक्षा-चिकित्सा, शहरी समाधान, बिजली व जलापूर्ति के प्रतिमान बढ़ गए। प्रदेश में परिवहन की मांग को जिस तरह निजी क्षेत्र ने समझा है, क्या उस स्तर का सोच सार्वजनिक क्षेत्र में पैदा हुआ। इतिहास गवाह है कि घाटे के बावजूद हर सरकार ने राजनीतिक बस डिपो बढ़ा दिए, जबकि मांग अलग जिरह करती रही। प्रदेश में कुछ ही सालों में निजी वोल्वो बसों का बेड़ा ढाई सौ के करीब पहुंच गया है, तो इस मांग को बाखूबी समझा गया। दूसरी ओर एचआरटीसी ने अगर 26 नई वोल्वो बसें जोड़ी भी, तो उनका तकाजा न बदला।

हिमाचल में पर्यटन क्षेत्र को समझने में भी सरकारी पक्ष की कमजोरी प्रदर्शित होती है। अब फोरलेन परियोजनाओं ने जिस तरह हाईवे टूरिज्म को बूस्ट दिया है, क्या उस परिप्रेक्ष्य में योजनाएं बनी हैं। आखिर टूरिस्ट जिस मौज मस्ती से या के लिए हिमाचल आना चाहता है, क्या हमने उस तस्वीर की आपूर्ति की है। हमने मंदिरों की आय को मंदिरों या श्रद्धालुओं की मांग पर आधारित नहीं किया, बल्कि इन्हें भी अनावश्यक रोजगार का गुलाम बना दिया। सदन की बहस में मांग और आपूर्ति का हिसाब करते हर सत्र गुजर जाता है, लेकिन हमारी नीतियां, कार्यक्रम और खाके पूरे नहीं होते।

आज भी विधायक अपने क्षेत्रों में पुलिस चौकी या थाने, फायर ब्रिगेड का दफ्तर, विभागीय दफ्तर, बस रूट, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति या किसी नए स्कूल-कालेज, डिस्पेंसरी या पशु औषधालय की मांग करते हैं, तो इसकी आपूर्ति का न्यायोचित फैसला होना चाहिए। राजनीति में सत्ता पक्ष ही वजीफे का हकदार नहीं होना चाहिए। आश्चर्य है कि सरकारें बदलते ही नीतियां बदल जातीं, स्वीकृत योजनाओं-परियोजनाओं की गति थम जाती। बजट का आबंटन हास परिहास का विषय या सियासत का शिलालेख बन जाता है, जबकि भौगोलिक मांग किसी अधूरे भवन की छाती पर मूंग दलती दिखाई देती है। प्रदेश की जरूरतें सियासी कद को नहीं बढ़ातीं, बल्कि इनकी कुशल आपूर्ति के लिए सख्त, संतुलित और पारदर्शी नीतियां चाहिएं। बिना छात्रों के स्कूल, बिना सवारी के बस रूट और बिना औचित्य के कालेज, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज या अनावश्यक दफ्तर खोलने से प्रदेश के प्रति वफादारी नहीं है।

ग्लोबल कंपनियां और भारतीय फर्में

डा. अश्विनी महाजन

हाल ही में भारत सरकार के व्यय विभाग ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में जेम (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) पर केंद्र सरकार की खरीद इकाइयों द्वारा जारी कंसल्टेंसी खरीद टेंडरों का अध्ययन किया, जिसमें पाया गया कि (1) टर्नओवर की अत्यधिक उच्च आवश्यकताएं निर्धारित की जाती रही हैं, (2) प्रमुख कर्मचारियों की योग्यता और अनुभव की तुलना में कंसल्टिंग फर्म के अनुभव को अधिक महत्व दिया गया था और (3) बोली लगाने वाली कंपनियों के वेतनभोगी कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या को पात्रता मानदंड के रूप में निर्धारित किया जाता रहा, जो काम को पूरा करने के लिए आवश्यक वास्तविक जनशक्ति से कहीं अधिक था।

लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, बल्कि भविष्य के लिए एक रोडमैप भी पेश किया और उन क्षेत्रों पर जोर दिया, जहां भारत को अपनी कोशिशें तेज करने की जरूरत है। इस संदर्भ में, उन्होंने भारतीय बैंकों और दवा कंपनियों से अपने-अपने क्षेत्रों में दुनिया की शीर्ष पांच कंपनियों में जगह बनाने का आह्वान किया। उन्होंने रेटिंग, कानून, अकाउंटिंग और कंसल्टिंग के क्षेत्रों में भारतीय फर्मों के खुद को स्थापित करने की जरूरत पर भी जोर दिया और कहा कि भारत के पास इन क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जरूरी टैलेंट और क्षमता दोनों मौजूद हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि यह पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री ने रेटिंग, कंसल्टिंग, कानूनी और अकाउंटिंग क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों की जरूरत पर जोर दिया है। इससे पहले भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने ये बातें उठाई हैं। एक ओर अंतरराष्ट्रीय कंसल्टिंग फर्में भारतीय सरकार को सलाह देती हैं और राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करती हैं, लेकिन साथ ही वे बड़ी ग्लोबल कंपनियों की भी सलाहकार होती हैं।

नतीजतन, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भारतीय सरकार को सलाह देते समय वे मल्टीनेशनल कंपनियों के हितों को प्राथमिकता नहीं देंगी। ग्लोबल कंसल्टिंग फर्मों के साथ काम करते समय भविष्य की योजनाओं की गोपनीयता और संबंधित डेटा की सुरक्षा भी चिंता का विषय है। इसलिए योजनाओं और डेटा के लीक होने का जोखिम उठाए बिना भारत के भीतर सही नीतियां बनाने के लिए घरेलू कंसल्टिंग फर्में स्थापित करना बहुत जरूरी है। इस क्षेत्र में ईमानदार सेवाओं की वैश्विक मांग भी है। अगर भारतीय कंपनियां अपनी विशेषज्ञता बढ़ाती हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवाएं देती हैं, तो देश काफी विदेशी मुद्रा कमा सकता है। जाहिर है, इस क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के आने से न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि यह विदेशी मुद्रा कमाने का एक बड़ा माध्यम भी बन सकती हैं। साथ ही ग्लोबल साजिशों का शिकार होने से भी बचा जा सकेगा।

यह समझना जरूरी है कि बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर दुनिया की प्रमुख कंसल्टिंग, रेटिंग, अकाउंटिंग और लॉ फर्मों के साथ काम करते हैं, चाहे वे भारत में काम करती हों या दुनिया में कहीं और, और कई कंपनियों में तो वे उनके सीईओ के तौर पर भी काम कर रहे हैं। भारत के बेहतरीन संस्थानों से पढ़े-लिखे और अंतरराष्ट्रीय अनुभव रखने वाले हमारे प्रोफेशनल्स किसी से कम नहीं हैं। ठीक इसीलिए प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि इस मामले में देश में टैलेंट या काबिलियत की कोई कमी नहीं है।

तो, ऐसा क्यों है कि इन सेक्टरों में भारत की कोई बड़ी कंपनियां नहीं हैं? इसे समझने के लिए हमें अपने इतिहास को देखना होगा। आजादी के बाद, हमारी आर्थिक नीतियां समाजवादी विचारधारा की ओर झुकी हुई थीं। उस समय नीति-निमार्ताओं का मानना था कि निजी क्षेत्र के पास जरूरी आर्थिक ताकत, टेक्नोलॉजी और जोखिम उठाने की क्षमता या सोच की कमी है। इसलिए आर्थिक विकास की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। ऐसे हालात में, आर्थिक नीति में निजी क्षेत्र को दूसरे दर्जे पर रखा गया। ऐसे माहौल में, कोई सोच भी कैसे सकता था कि कोई भारतीय लॉ फर्म, रेटिंग एजेंसी या कंसल्टिंग और अकाउंटिंग कंपनी ग्लोबल स्तर पर पहचान बनाएगी और दुनिया भर में अपना नाम कमाएगी। 1991 के बाद अपनाई गई भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण (एलपीजी) की नीतियों के तहत भी ग्लोबलाइजेशन का ही बोलबाला रहा। सोच यह थी कि देश ग्लोबल कंपनियों की मदद से आगे बढ़ सकता है- चाहे वह टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग या सेवा क्षेत्र हो। आत्मविश्वास की कमी के कारण भारतीय नीति-निमार्ताओं ने घरेलू कंसल्टिंग, कानूनी, अकाउंटिंग और रेटिंग एजेंसियों को विकसित करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। इसके अलावा जरूरी प्रोफेशनल टैलेंट और काबिलियत होने के बावजूद, भारतीय प्रोफेशनल्स को बड़ी कंसल्टिंग कंपनियां बनाने में संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि घरेलू नियम और कानून अक्सर इसमें बाधा बनते हैं। वास्तविकता तो यह है कि आत्मविश्वास की कमी के कारण, भारतीय नीति-निमार्ताओं ने कभी भी घरेलू कंसल्टिंग, कानूनी, अकाउंटिंग और रेटिंग एजेंसियां विकसित करने के विचार पर गंभीरता से विचार नहीं किया।

जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान भारतीय कंसल्टिंग फर्मों की स्थापना के मुद्दे पर गया, तो यह महसूस किया गया कि इसके लिए महत्वपूर्ण नियामक बदलावों की आवश्यकता होगी। यह देखा गया कि मौजूदा नियम, विशेष रूप से वकीलों और वित्तीय पेशेवरों के लिए, उन्हें कॉर्पोरेट संरचनाएं अपनाने, बहु-विषयक (मल्टी डिसिप्लिनरी) प्रैक्टिस करने और विदेशी सहयोग करने में बाधा बन रहे हैं। हालांकि यह धारणा है कि केवल बहुराष्ट्रीय फर्मों के पास ही विभिन्न देशों में काम करने का अनुभव, अपनी खुद की रिसर्च और विशेष ज्ञान होता है। इसके लिए घरेलू पेशेवरों को शुरूआत करने के लिए उचित अवसर दिए जाने की सख्त जरूरत है। जिसके बिना इन क्षेत्रों में भारत की अपनी कंपनियों का उदय संभव नहीं। हमारी नौकरशाही भारतीय कंसल्टिंग, कानूनी और अकाउंटिंग फर्मों के विकास में सबसे बड़ी बाधा रही है। उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के नाम पर, भारतीय फर्मों, विशेष रूप से कंसल्टिंग क्षेत्र में, को जानबूझकर सरकारी खरीद अनुबंधों (प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स) के लिए प्रतिस्पर्धा से बाहर रखा जाता रहा है। उदाहरण के लिए कुछ करोड़ रुपए के अनुबंधों के लिए सरकारी टेंडरों में अक्सर यह शर्त रखी जाती थी कि बोली लगाने वाली इकाई का टर्नओवर कई हजार करोड़ रुपए होना चाहिए। इसके अलावा सरकारी खरीद और सेवाओं के लिए कर्मचारियों की संख्या या योग्यता से संबंधित प्रतिबंधात्मक शर्तें अक्सर लगाई जाती थीं। वास्तव में, ऐसी प्रतिबंधात्मक शर्तें न केवल सेवाओं की खरीद में, बल्कि वस्तुओं की खरीद में भी आम बात रही हैं।

किसानों-पशुपालकों के समक्ष चुनौतियां

रामलाल पाठक

कई जगह किसानों की आईडी नहीं बन रही है। शुरू में किसान लोकमित्र केंद्रों में चक्कर काटते रहे, लेकिन नेट की समस्या या अन्य तकनीकी कारणों से अनेक किसानों को यह सम्मान निधि भी नहीं मिल रही है। जानकारी के अभाव में ग्रामीणों को जिला एवं तहसील मुख्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्हें सीधा लोकमित्र केंद्रों में भेजा जाता है। जब काम नहीं होता तो वे वापस अपने घर आ जाते हैं। इससे उनका पूरा दिन बर्बाद हो जाता तथा बेवजह पैसा भी खर्च होता है। कुछ मिलने के बजाय जेब से भी जा रहा है। इस साल एक और नई दिक्कत यह आई कि फसल के लिए किसानों को रासायनिक खाद चाहिए होती है। इसके लिए किसान की जमीन का खसरा नंबर जरूरी कर दिया है। इसके बिना खाद नहीं मिली।

हमारे देश की 75 प्रतिशत से अधिक आबादी गांवों में रहती है। कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय होने के कारण उन्हें अपनी मेहनत के अनुसार आय नहीं हो रही है। केन्द्र या प्रदेश सरकार इस वर्ग के समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करके रात दिन कड़ी मेहनत करके कृषक देश की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। किसानों एवं पशुपालकों के सामने अनेक चुनौतियां हैं। नतीजतन अब उपजाऊ भूमि बंजर होने लगी है तथा पशुपालकों के ज्यादातर पशु सडकों, गलियों और चैराहों में भटक रहे हैं। ग्रामीणों को लग रहा है कि अब खेतीबाड़ी करना और पशुपालन व्यवसाय घाटे का सौदा हो गया है। इसलिए अब ग्रामीण युवा रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। इसलिए कृषि एवं पशुपालन का काम न के बराबर हो गया है। पहले शहरों के लिए गांव से अनाज और दूध वितरित होता था। अब स्थिति यह हो गई है कि शहरों से आटा, दाल, सब्जी और फल इत्यादि गांव के लिए वितरित हो रहे हैं। यह भी तर्कसंगत रहा कि खेतीबाड़ी एवं पशुपालन व्यवसाय से ग्रामीण स्तर की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती रही है, जबकि देश के विकास का रास्ता गांव से होकर गुजरता है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्र जितने विकसित होंगे, देश की आर्थिक व्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी।

पशुपालन से कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक दूध की आपूर्ति हो रही है। स्वस्थ समाज के लिए जितना अन्न आवश्यक है उतना ही दूध भी आवश्यक है। एक लोक कहावत ह्यगाय न बच्छी नींद पई अच्छीह्न प्रचलित है। यानी कृषि एवं पशुपालन ग्रामीण जीवन शैली का आधार है। यदि किसान के पास पशु नहीं होंगे तो कृषि कार्यों में उसकी सक्रियता नहीं रहेगी। उपरोक्त लोक कहावत का यह अर्थ है कि यदि किसान के पास गाय या बछड़ी अर्थात पशु नहीं होंगे तो वह कोई मेहनत नहीं करेगा। इसलिए उसकी नींद भी समय पर नहीं खुलेगी। उसे चिंता नहीं होगी कि उसने पशुओं के लिए घास-पानी की व्यवस्था करनी है। डिजिटल इंडिया के कार्यान्वयन के बाद केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार आए दिन किसानों के लिए नई-नई समस्याएं खड़ी कर रही है तथा थोड़े से अनुदान के लिए नियम इतने कड़े कर दिए हैं कि किसान को खेत में काम करने के बजाय औपचारिकताएं पूरी करने के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है। इससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फसल की बुआई के समय किसान का एक एक पल बहुमूल्य होता है। यह काम ज्यादातर बारिश पर ही निर्भर करता है। बारिश के पानी से खेत में नमी थोड़े ही समय के लिए रहती है। पर्याप्त मात्रा में नमी न होने से बीज में अंकुर नहीं फूटते। ऐसी स्थिति में किसान को अगली बारिश के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कई बार समय पर बारिश नहीं होती। इसलिए फसल पर शुरू से ही संकट मंडराने लगता है। केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों के लिए किसानों को सालाना 6 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। यह राशि साल में तीन किस्तों में मिलती है। शुरू में उन लोगों को भी किसान निधि का लाभ मिल गया, जिनके पास एक बीघे से कम भूमि थी, लेकिन उन किसानों को यह राशि नहीं मिली जिनके पास पांच बीघे से अधिक जमीन थी। कुछ सुधार होने के बाद किसानों को आईडी बनाने के चक्कर में डाल दिया। इसके लिए किसान की भूमि ऑनलाइन होनी जरूरी है। कई जिलों में बनी नई तहसीलों और उप-तहसीलों में किसानों की जमीन ऑनलाइन नहीं हुई। यदि हुई है तो उसमें दिक्कत आ रही है। इससे असंख्य किसानों को इस सम्मान राशि से वंचित रहना पड़ रहा है।

कई जगह किसानों की आईडी नहीं बन रही है। शुरू में किसान लोकमित्र केंद्रों में चक्कर काटते रहे, लेकिन नेट की समस्या या अन्य तकनीकी कारणों से अनेक किसानों को यह सम्मान निधि भी नहीं मिल रही है। जानकारी के अभाव में ग्रामीणों को जिला एवं तहसील मुख्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्हें सीधा लोकमित्र केंद्रों में भेजा जाता है। जब काम नहीं होता तो वे वापस अपने घर आ जाते हैं। इससे उनका पूरा दिन बर्बाद हो जाता तथा बेवजह पैसा भी खर्च होता है। कुछ मिलने के बजाय जेब से भी जा रहा है। इस साल एक और नई दिक्कत यह आई कि फसल के लिए किसानों को रासायनिक खाद चाहिए होती है। इसके लिए किसान की जमीन का खसरा नंबर जरूरी कर दिया है। इसके बिना खाद नहीं मिली। कई किसानों की सहकारी सभाएं और पटवारखाना अलग अलग दिशा में हैं। उन्हें भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कई किसानों के इस काम के लिए दो-दो दिन लग गए। आज खेतीबाड़ी का काम अनेक चुनौतियों से भरा है। जमीन में बड़ी तेजी से फैलता खरपतवार तथा उपजाऊ भूमि की लगातार घटती उर्वरकता सबसे गंभीर समस्याएं हैं। दशकों पहले भी किसान खेती करते थे। उस समय भले ही अनाज की अधिक पैदावार नहीं थी लेकिन किसानों को किसी प्रकार का झंझट नहीं था। रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयां भी नहीं होती थी। किसान अपने खेत में गोबर खाद डालते थे तथा कीटनाशक की जगह गौमूत्र और राख आदि फैंकते थे। उससे फसल अच्छी हो जाती थी। खरपतवार से फसलों को पूरी तरह पोषक तत्व और नमी नहीं मिलती और न ही पर्याप्त मात्रा में धूप ही मिल पाती। दूसरी ओर मिट्टी की उर्वरकता में निरंतर गिरावट आने से उत्पादन प्रभावित हो रहा है।

यदि इन दोनों समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं किया गया, तो कृषि उत्पादन, किसानों की आय और देश की खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। किसानों का मानना है कि कृषि क्षेत्र में घुसी मल्टीनेशनल कम्पनियों ने ऐसी चालाकी की है कि यदि आप बीज किसी दूसरी कम्पनी के लेंगे तथा कीटनाशक दवाइयां किसी अन्य कम्पनी की होगी तो फसल ठीक नहीं होगी। आज यह समस्या भी भयंकर हो गई है कि कीटनाशक दवाइयों के बिना कोई भी फसल नहीं होती। चाहे सब्जियां हो या फल, छिडकाव जरूरी हो गया है। यही नहीं, यदि अब घासनियों में छिडकाव नहीं करेंगे तो घास काटना भी मुश्किल होता है। इससे पशु पालकों समस्या गम्भीर हो गई है। तेजी से फैल रहे खरपतवार की समस्या के बारे में कृषि वैज्ञानिकों को भी सोचना चाहिए।

न्यूज ब्रीफ

स्वच्छ स्कूल प्रतियोगिता का आज से आगाज

ग्वालियर। *नगर निगम द्वारा शहर के 22 (शासकीय,अर्ध शासकीय, केंद्रीय) स्कूलों के बीच कराए जा रहे स्वच्छ स्कूल प्रतियोगिता के तहत 2 सितंबर को सुबह 9 बजे से बालभवन में प्री कॉम्पिटिशन का आयोजन किया जाएगा। इसमें सिलेक्ट हुए बच्चों के बीच 3 सितंबर को राजमाता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय के दंतोपथ ठेंगड़ी भवन में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।*
उल्लेखनीय है कि अगस्त माह से अपर आयुक्त टी प्रतीक राव के निर्देशन में शहर के 22 शासकीय एवं प्राइवेट स्कूलों में नगर निगम की स्वच्छता टीमें पहुंचकर बच्चों को स्वच्छता की जानकारी दे रही हैं। साथ ही बच्चों को स्वच्छ सर्वेक्षण के माप दण्डों के बारे में भी बताया गया है।

वृक्षारोपण से पर्यावरण संरक्षण और हरियाली का दिया संदेश

ग्वालियर। *जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंगलवार को सेशन हाउस, जिला न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री ललित किशोर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में जिला न्यायालय में पदस्थ सभी न्यायाधीशों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) श्री नवीन शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री प्रशांत पाण्डेय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री पुष्पेन्द्र सिंह सहित अन्य न्यायाधीशों ने पौधरोपण किया। इस अवसर पर पर्यावरण को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषणमुक्त बनाए रखने के लिए लगाए गए पौधों की उचित देखभाल एवं संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के प्रति*

गोबर नाली में बहाने पर भैंस डेयरी संचालकों से वसूला जुर्माना

ग्वालियर। *शहर स्वच्छ व साफ रहे इसलिए गंदगी फैलाने वालों, अमानक पॉलीथिन, गोबर नालियों में बहाने वालों एवं भवन सामग्री सडक पर डालने वालों पर निगम द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है।*
निगम आयुक्त श्री अभिषेक चौधरी के निर्देशानुसार गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। जिसके तहत आज स्वच्छता टास्क फोर्स टीम द्वारा वार्ड क्रमांक 29 गायत्री विहार कॉलोनी का निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण के दौरान गायत्री विहार में भैंस डेयरी संचालकों द्वारा सीवर लाइन में गोबर बाहर जा रहा था तभी मौके स्थल पर मौके डेयरी संचालकों को समझाइए दी गई अन्यथा ऐसी स्थिति पाई गई तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी एवं जुर्माना भी लगाया जाएगा । इसके ही उपरांत पिंटू पार्क स्थित द रॉयल क्लास होटल पर भी निरीक्षण किया गया होटल पर निरीक्षण के दौरान पाया गया कि होटल संचालक द्वारा भी होटल किचन बेस्ट सीवर लाइन में बहाया जा रहा था तभी संचालक पर 2000 का जुर्माना लगाया गया ।

बानमोर तक उखाड़ी जाएगी 20 किमी पटरी

120 साल पुरानी विरासत का अंत: रेलवे बोर्ड ने हेरिटेज ट्रेन प्रस्ताव किया खारिज

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

अंचल की ऐतिहासिक विरासत और ग्वालियर की पहचान रही 120 साल पुरानी नैरोगेज ट्रेन अब कभी पटरियों पर दौड़ती नजर नहीं आएगी। लगभग छह दशक से अधिक समय तक शहरवासियों की जीवनरेखा रही देश की सबसे पतली (2 फीट चौड़ी) पटरी वाली इस ट्रेन को हेरिटेज के रूप में सहेजने की बची-कुची आखिरी उम्मीद भी अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। रेलवे बोर्ड ने हेरिटेज ट्रेन चलाने के प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया है। इसके साथ ही रेलवे ने ग्वालियर से बानमोर तक फैले करीब 20 किलोमीटर लंबे नैरोगेज ट्रैक को पूरी तरह उखाड़ने का फैसला किया है, जिसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सिंधिया रियासतकाल में शुरू की गई यह नैरोगेज ट्रेन ग्वालियर के समृद्ध परिवहन इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा रही है। करीब छह साल पहले जब इसका परिचालन बंद किया गया, तब स्थानीय नागरिकों और धरोहर प्रेमियों को उम्मीद थी कि कम से कम इसके कुछ हिस्से को हेरिटेज ट्रेन के रूप में बचा लिया जाएगा। योजना बनी थी कि घोसीपुरा से बानमोर गांव के बीच दो कोच वाली एक हेरिटेज ट्रेन चलाई जाएगी। इसी योजना की संभावना तलाशने के लिए पिछले साल रेलवे बोर्ड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (हेरिटेज) आशिमा मेहरोत्रा और डिप्टी डायरेक्टर राजेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर विस्तृत सर्वे भी किया था। हालांकि, तकनीकी जटिलताओं और व्यावहारिक पहलुओं की गहन पड़ताल के बाद रेलवे बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचा कि इस रूट पर हेरिटेज ट्रेन चलाना संभव नहीं है। नैरोगेज ट्रैक हटने के बाद अब इस बहुमूल्य जमीन के कायाकल्प की तैयारी शुरू हो चुकी है। जमीन के पुनर्विकास की पूरी जिम्मेदारी रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंपी गई है: ग्रीन बेल्ट और पौधरोपण: RLDA की टीम ग्वालियर से बानमोर तक पूरी जमीन का सर्वे कर रही है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ हिस्सों को 'ग्रीन बेल्ट' के रूप में विकसित करने पर काम चल रहा है, जिसके लिए वन विभाग से निरंतर चर्चा जारी है। कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स: ट्रैक की जो जमीन प्राइम लोकेशन पर स्थित है, उसका व्यावसायिक इस्तेमाल किया जाएगा। भविष्य में वहां बड़े कॉमर्शियल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विकसित करने की योजना है। सार्वजनिक विकास के लिए लैंड एक्सचेंज: शहर के विकास कार्यों की आवश्यकतानुसार स्थानीय प्रशासन के साथ 'लैंड एक्सचेंज प्रोग्राम' के तहत जमीन के आदान-प्रदान पर भी विचार किया जाएगा। 'पूरा नैरोगेज ट्रैक हटाया जाएगा। इसके बाद सार्वजनिक विकास कार्यों के लिए प्रशासन को जरूरत के अनुसार लैंड एक्सचेंज प्रोग्राम में जमीन देने पर विचार होगा। RLDA ग्रीन बेल्ट के लिए स्थान चिह्नित कर रहा है। '

महंगाई, विदेशी कर्ज, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हिंदू महासभा आज करेगी सद्बुद्धि यज्ञ

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

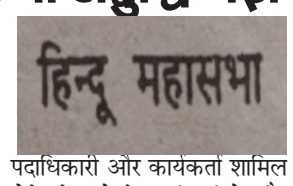

प्रदेश और देश में बढ़ती महंगाई, विदेशी कर्ज, कानून व्यवस्था की स्थिति तथा धार्मिक स्थलों से जुड़े मुद्दों को लेकर हिंदू महासभा ने विरोध का ऐलान किया है। संगठन की ओर से 2 सितंबर को ग्वालियर में सद्बुद्धि यज्ञ आयोजित किया जाएगा। हिंदू महासभा के नेताओं के अनुसार, यह कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री के ग्वालियर आगमन के दौरान आयोजित किया जा रहा है। संगठन के कार्यकर्ता काले झंडों के साथ अपनी मांगों और विरोध को सामने रखेंगे। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों के अनुसार, सद्बुद्धि यज्ञ का उद्देश्य सरकार का ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करना है, जिन्हें संगठन जनहित और हिंदू समाज से जुड़े महत्वपूर्ण विषय मानता है। संगठन ने महंगाई कम करने, विदेशी कर्ज से मुक्ति, कानून व्यवस्था में सुधार और धार्मिक स्थलों के संबंध में अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाने का निर्णय लिया है। संगठन की ओर से बताया गया है कि 2 सितंबर को दोपहर 2 बजे दौलतगंज स्थित हिंदू महासभा भवन में सद्बुद्धि यज्ञ आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। नेताओं ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कार्यक्रम में पहुंचकर आंदोलन को सहयोग देने की अपील की है। हिंदू महासभा के नेताओं का कहना है कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराया जाएगा। इसी क्रम में काले झंडों के माध्यम से सरकार की नीतियों के प्रति असहमति जताई जाएगी।

महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना

हिंदू महासभा ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। संगठन का कहना है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर आम परिवारों के बजट पर पड़ रहा है। खाद्य सामग्री, रोजमर्रा की जरूरतों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से आम आदमी की आर्थिक परेशानियां बढ़ रही हैं। संगठन ने सरकार से महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।

नगर निगम मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में लगी मोबाइल कोर्ट, मौके पर हुई 28 प्रकरणों में कार्रवाई

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

नगर निगम मजिस्ट्रेट श्री निशांत मिश्रा के नेतृत्व में संचालित मोबाइल कोर्ट द्वारा शहर में गंदगी फैलाने और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इस दौरान नगर निगम और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 67500 रुपये का जुर्माना लगाया। जिसमें धारा 248 के तहत 6 प्रकरण एवं धारा 322 के तहत 22 प्रकरण बनाए। मोबाइल कोर्ट में कुल 28 प्रकरण बनाए गए तथा 03 प्रकरण जिसमें जुर्माना राशि जमा करना स्वीकार नहीं किया गया है उन्हें माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
नोडल अधिकारी विधि श्री अनूप लिटोरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्रवाई के दौरान थाटीपुर क्षेत्र में बसीम मीट शॉप, खान मटन शॉप एवं कुरैशी मीट शॉप पर धारा 248 गंदगी फैलाने पर 2000-2000 रूपये का जुर्माना किया गया। इसके पश्चात गोविंदपुरी क्षेत्र में होटल मोजिक पर धारा 248 के तहत 5000 रूपये का जुर्माना वहीं गोले का मंदिर क्षेत्र में श्रीराम मिष्ठान भंडार पर धारा 322 एवं 248 के तहत 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया। इसके पष्चात मुरार बारादरी क्षेत्र में धारा 322 के तहत खाटू श्याम फर्नीचर पर 5000 रूपये का जुर्माना, साहिल स्टील फर्नीचर पर 5000 रूपये का जुर्माना किया गया।

युवक का अपहरण कर पत्नी से मांगी 3 लाख की फिरौती, 18 घंटे में पुलिस ने छुड़ाया

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

ग्वालियर थाना क्षेत्र के तानसेन नगर से दो परिचितों द्वारा एक युवक का अपहरण कर पत्नी से 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी । पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 18 घंटे के भीतर मोबाइल लोकेशन के आधार पर शिवपुरी के बैराड़ से युवक को सकुशल मुक्त करा लिया और मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस के अनुसार , तानसेन नगर निवासी वीरू करण पुत्र रामशंकर करण एक निजी कंपनी में नौकरी करता है। सोमवार दोपहर वह घर पर था, तभी उसके दो परिचित यवक वहां पहुंचे और उसे नौकरी करता है। सोमवार दोपहर वह घर पर था, तभी उसके दो परिचित युवक वहां पहुंचे और उसे अपने साथ ले गए।
शाम को वीरू के मोबाइल नंबर से उसकी पत्नी के फोन पर वाट्सऐप मैसेज आया। इसमें बताया गया कि वीरू का अपहरण कर लिया गया है और उसे छोड़ने के बदले 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। मैसेज मिलते ही परिजन घबरा गए और तुरंत ग्वालियर थाने पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। अपहरण और फिरौती की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी प्रशांत शर्मा और एसआई अजय सिकरवार के नेतृत्व में दो टीमें गठित की गईं। पुलिस ने तानसेन नगर और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसमें दो संदिग्ध युवक वीरू को अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने वीरू के मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस की, जो शिवपुरी जिले के बैराड़ में मिली।

ऑपरेशन फास्ट 2.0 में बड़ी कार्रवाई, फर्जी सिम बेचने वालों पर 9 केस दर्ज

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

पुलिस महानिदेशक म.प्र. के आदेशानुसार एवं राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देशित ऑपरेशन फास्ट 2.0 संदिग्ध पीओएस/सिम धारक/एजेंट्स/फेक सिम यूजर एवं अन्य संदिग्धों के विरूद्ध त्वरित वैधानिक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया था। इसी क्रम में ऑपरेशन फास्ट 2.0 के नोड़ल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर (मध्य/यातायात) सुजावल जग्गा(भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर (पूर्व) डॉ0 शिवेश सिंह बघेल (रापुसे) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयराज कुबेर (रापुसे) के द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने थानों में संदिग्ध पीओएस /सिम धारक/ एजेंट्स/ फेक सिम यूजर एवं अन्य के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कराने हेतु निर्देषित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के परिपालन में डीएसपी अपराध नागेन्द्र सिंह सिकरवार एवं डीएसपी अपराध मनीष यादव के कुशल मार्गदर्शन में विभिन्न थानों एवं तकनीकी सेल की सयुक्त टीमें बनाकर एनसीआरपी पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की जॉच कर संदिग्ध पीओएस, सिम धारक, एजेंट्स, फेक सिम यूजर्स एवं अन्य संदिग्धों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु लगाया गया।

निवेश के नाम पर 1.63 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के प्रकरण में एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

ग्वालिय। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर धर्मवीर सिंह (भापुसे) के निर्देष पर साइबर अपराधों में संलिप्त आरोपियों एवं साइबर फ्रॉड के लिए म्यूल बैंक खातों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में साइबर क्राइम विंग ग्वालियर पुलिस द्वारा निवेश के नाम पर हुई 1,63,19,900/- रूपये की साइबर ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बड़ी संख्या में डेबिट/प्रीपेड कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक एवं मोबाइल फोन जप्त किया गया है। घटना का संक्षिप्त विवरण:- फरियादी मनीष जैन निवासी रामदास घाटी, ए.बी.रोड बहोड़ापुर ग्वालियर द्वारा थाना क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 22.04.2026 से 20.07.2026 के मध्य निवेश के नाम पर उसके साथ धोखाधड़ी कर कुल 1,63,19,900/- रूपये की ठगी की गई है। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना क्राइम ब्रांच में अपराध क्रमांक 31/2026 धारा 318(4),319(2) बीएनएस एवं 66(डी) आईटी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री सुजावल जग्गा(भापुसे) को उक्त प्रकरण में वांछित साइबर अपराधियों की पतारसी कर पकडवाने हेतु निर्देषित किया गया।

राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने के विरोध में कांग्रेस का धरना

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा संसद में छुआछूत, सामाजिक भेदभाव एवं दलित सम्मान जैसे गंभीर विषयों को उठाने पर उनके खिलाफ राजनीतिक दुर्भावना से एफआईआर दर्ज किए जाने के विरोध में शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा फूलबाग स्थित गांधी उद्यान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेसजनो ने शांतिपूर्ण उपवास एवं धरना आयोजित कर विरोध दर्ज कराया गया।
उपवास आंदोलन में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव ने कहा कि भाजपा की राजनीति लगातार संविधान कानून का दुरुपयोग, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और विपक्ष की आवाज को दबाने का माध्यम बनती जा रही है। उपवास धरने में पूर्व अध्यक्ष चन्द्र मोहन नागोरी, विधायक सहाब सिंह गुर्जर, प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा, दशरथ सिंह गुर्जर, ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष प्रभूदयाल जौहरे, संगठन महामंत्री इब्राहिम पठान, जेएच जाफरी, राजेन्द्र सिंह नाती, वीर सिंह तौमर, हेवरन सिंह कंसाना, जयराज सिंह चौहान, हमीद खां उस्मानी, चतुर्भुज धनोलिया, राकेश अग्रवाल, रामबाबू श्रीवास, ब्लॉक अध्यक्ष महेश धनोलिया, राकेश कुशवाह, अनुप शिवहरे, संदीप यादव, धर्मवीर राठौर, अंसार अली, कुलदीप व्यास, श्रीमती रेखा जाटव, श्रीमती लक्ष्मी माथुर, राकेश शर्मा, सहित अनेक कांग्रेसजन सम्मलित थे।

02 सितम्बर को मेला ग्राउंड में होगा भव्य बलराम महोत्सव

बलराम जयंती पर ग्वालियर में गूंजेगा किसान सम्मान का जयघोष : यादव

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

भगवान बलराम जयंती एवं किसान दिवस के अवसर पर 02 सितम्बर को ग्वालियर के मेला ग्राउंड में आयोजित होने जा रहे भव्य बलराम महोत्सव को लेकर ग्रामीण अंचलों में उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। महोत्सव को लेकर गांव-गांव बैठक कर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अपेक्स बैंक प्रशासक एवं कार्यक्रम संयोजक श्री महेंद्र सिंह यादव ने ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर किसानों और ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया तथा उन्हें परिवार सहित महोत्सव में शामिल होने का आमंत्रण दिया।
'यह सिर्फ उत्सव नहीं, अन्नदाता के सम्मान का महापर्व है ' ग्रामीणों से संवाद करते हुए श्री महेंद्र सिंह यादव ने कहा कि बलराम महोत्सव किसान, खेती, गांव और हमारी समृद्ध कृषि संस्कृति को समर्पित पर्व है। भगवान बलराम भारतीय कृषि परंपरा में किसान शक्ति और परिश्रम के प्रतीक हैं। उनकी जयंती पर आयोजित यह आयोजन अन्नदाता के प्रति सम्मान व्यक्त करने के साथ-साथ नई पीढ़ी को अपनी ग्रामीण परंपराओं और कृषि संस्कृति से जोड़ने का अवसर है। उन्होंने बताया कि नंदलाल बाल कल्याण समिति द्वारा वर्ष 2006 से निरंतर बलराम

जयंती महोत्सव की परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी परंपरा को व्यापक रूप देते हुए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश के प्रत्येक जिले में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं और इसी क्रम में अब तक लगभग 22 जिलों में आयोजन हो चुके हैं। गांव-गांव पहुंचा आमंत्रण, किसानों में दिखा उत्साह जनसंपर्क अभियान के दौरान श्री यादव ने जलालपुर, मालनपुर, गंगापुर, पुरानी छावनी, रायरू, रायरू फार्म, बरऊआ, मिलावली, जिनावली, निरावली, गजीपुरा, नायकपुरा, तिलघना, सीता का पुरा, शिकरवार का पुरा, राम प्रसाद का पुरा, छोटे का पुरा, विलपुरा, जिगसौली, कुलैथ, मेहदपुर, महेश्वरा, खेरिया माता की, सिगोरा, टेहलरी, थर और शंकरपुर सहित अनेक गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीणों में 02 सितम्बर को ग्वालियर पहुंचने को लेकर खासा उत्साह नजर आया। श्री यादव ने सभी से आग्रह किया कि परिवार सहित मेला ग्राउंड पहुंचें और किसान सम्मान के इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनें।बलराम महोत्सव के माध्यम से किसानों के सम्मान, कृषि विकास, ग्रामीण संस्कृति और किसान शक्ति का संदेश दिया जाएगा। आयोजन को लेकर ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र में तैयारियां और जनसंपर्क अभियान तेजी से जारी है।

अल्काराज की 139 दिन बाद जीत से वापसी

यूएस ओपन के दूसरे राउंड में पहुंचे, सबालेंका भी जीतीं

यूएस (एजेंसी)। यूएस ओपन 2026 में डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्काराज ने 139 दिन बाद सिंगल्स कोर्ट पर जीत के साथ वापसी की। अल्काराज कलाई की चोट के कारण चार महीने से ज्यादा समय तक टेनिस से दूर थे। स्पेन के खिलाड़ी ने न्यूयॉर्क के आर्थर एश स्टेडियम में रूस के रोमन सफीउलिन को 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वहीं, विमेंस सिंगल्स में दो बार की डिफेंडिंग चैंपियन आर्यना सबालेंका ने कैमिला ओसोरियो को 6-2, 6-4 से हराया।अल्काराज ने चोट के कारण इस दौरान फ्रेंच ओपन और विंबलडन में हिस्सा नहीं लिया था। मैच के दौरान वह दाहिने हाथ पर कम्प्रेशन स्लीव पहनकर खेले।

स्वियातेक और नोस्कोवा भी जीतीं

छठी ग्रैंड स्लैम चैंपियन इगा स्वियातेक ने चीन की वांग शियू को 6-2, 6-3 से हराकर शुरुआत की। विंबलडन चैंपियन लिंडा नोस्कोवा ने अमेरिका की केटी वोलीनेट्स को 7-5, 6-1 से हराया। वहीं, पिछले साल यूएस ओपन की रनर-अप अमांडा अनिसिमोवा ने अपने 25वें जन्मदिन पर एशलिन क्रूगर को 6-1, 6-3 से शिकस्त दी।

सबालेंका ने ओसोरियो को हराया

महिला सिंगल्स में दुनिया की नंबर-1 आर्यना सबालेंका ने कैमिला ओसोरियो को 6-2, 6-4 से हराया। इसके साथ ही उनका लगातार तीसरा यूएस ओपन खिताब जीतने का अभियान जारी रहा। वह ओपन एरा में लगातार तीन यूएस ओपन खिताब जीतने वाली तीसरी महिला बन सकती हैं। उनसे पहले सेरेना विलियम्स और क्रिस एवर्ट ऐसा कर चुकी हैं। पहला सेट आसानी से जीतने के बाद सबालेंका को दूसरे सेट में संघर्ष करना पड़ा। हालांकि 4-4 के स्कोर के बाद वापसी कर मैच अपने नाम कर लिया। अगले दौर में उनका सामना रूस की क्वालिफायर पोलिना यात्सेंको से होगा।

● **अल्काराज बोले- लय हासिल करने के लिए और मैच खेलने की जरूरत -** अल्काराज की वापसी जीत शानदार रही, लेकिन सर्विस में उन्हें संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कहा कि चार महीने बाद वापसी में उन्हें मैच फिटनेस को लेकर थोड़ी चिंता थी। उन्हें यह भी संदेह था कि वह पांच सेट का मैच खेल पाएंगे या नहीं। जीत के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें लय हासिल करने के लिए अभी और मैच खेलने की जरूरत है। कार्लोस अल्काराज 2004 से 2008 के बीच लगातार पांच बार खिताब जीतने वाले रोजर फेडरर के बाद यूएस ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब लगातार दूसरी बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बनने की कोशिश में हैं।

सूर्यवंशी दूसरी पारी में 40 रन बनाकर आउट

दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में ईस्ट जोन- 94/3, सेंट्रल जोन ने 159 रन का टारगेट दिया

नईदिल्ली (एजेंसी)। दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में ईस्ट जोन के उपकप्तान वैभव सूर्यवंशी दूसरी पारी में 40 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने सेंट्रल जोन के खिलाफ अपनी पारी में 3 चौके और 2 छक्के लगाए। सेंट्रल जोन की दूसरी पारी 158 रन पर सिमट गई। ईस्ट जोन को टेस्ट मैच जीतने के लिए 159 रन का टारगेट मिला है। इसके जवाब में टीम ने 27 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। कुमार कुशाग्र 16 और कप्तान ईशान किशन 1 रन बनाकर खेल रहे हैं।

सेंट्रल जोन ने 37 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे

सेंट्रल जोन की शुरुआत खराब रही और 37 रन तक टीम के तीन विकेट गिर गए। कप्तान रजत पाटीदार 5 और रिंकू सिंह 20 रन ही बना सके। 95 रन तक 7 विकेट गंवाने के बाद अरशद खान ने लोअर ऑर्डर के साथ मिलकर टीम को 150 रन के पार पहुंचाया। हालांकि टीम 158 रन पर ही सिमट गई। अमन मोखाड़े ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 41 रन बनाए। अरशद खान ने 25 और हर्ष दुबे ने 24 रन की पारी

मुकेश कुमार को 4, शमी को 3 विकेट - ईस्ट जोन की ओर से मुकेश कुमार सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 12 ओवर में 44 रन देकर 4 विकेट लिए। मोहम्मद शमी ने 3, जबकि अभिजीत सरकार, अनुकूल रॉय और कुनैन कुरैशी ने 1-1 विकेट लिया।

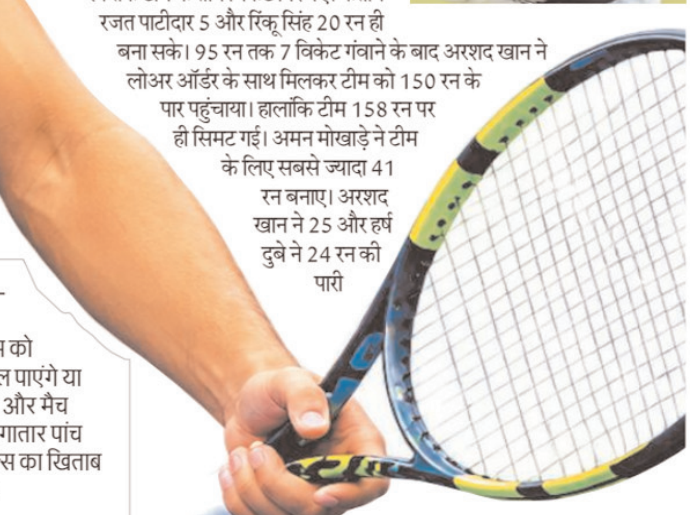

मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया

इंस्टाग्राम पर इमोशनल पोस्ट की, लिखा- यह फैसला बेहद मुश्किल और दर्दनाक

मेसी ने पोस्ट में क्या लिखा फैसला तकलीफदेह था

- मेसी ने लिखा, 'यह फैसला लेना तकलीफदेह था और आज भी दिल के अंदर तक दुख देता है, लेकिन मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है। मैंने हमेशा अपना सब कुछ दिया है। सिर्फ उन पिछले कुछ सालों में नहीं, जब हमने सब कुछ जीता, बल्कि उससे पहले भी।'
- मैंने इस जर्सी के लिए हमेशा संघर्ष किया। मैदान पर अपना सब कुछ छोड़ा, ताकि आपको खुशी दे सकूं। फुटबॉल के जरिए आपको अर्जेंटीनियन होने पर गर्व महसूस करा सकूं।
- समय कम बचा है और अध्याय खत्म होते हैं। यह भी ऐसा ही एक अध्याय है, जो मुझे बहुत दुख देता है। मुझे राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बनना पसंद था, पसंद है और हमेशा रहेगा।
- मैंने अपने पास मौजूद सब कुछ दे दिया है। अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसके अलावा, कई बेहतरीन युवा खिलाड़ी आ रहे हैं, जो यहां होने के हकदार हैं।

अर्जेंटीना को 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप जिताया

मेसी अपने देश के सबसे ज्यादा गोल करने वाले और सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2005 में अर्जेंटीना के लिए डेब्यू किया था। वे टीम के लिए 6 वर्ल्ड कप खेले चुके हैं।

ब्राजील (एजेंसी)। मेसी ने 2016 में भी संन्यास लिया था। तब वे 3 वर्ल्ड कप में कप्तानी कर चुके थे, लेकिन जीत नहीं सके थे। उन्होंने अपना फैसला बदला और टीम को 2022 का वर्ल्ड कप जिताया। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल को अलविदा कह दिया है। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया पर हाथ से लिखे नोट की तस्वीर के साथ संन्यास का ऐलान किया। 39 साल के मेसी ने बताया कि फाइनल के 2 दिन बाद 21 जुलाई को ही उन्होंने संन्यास का फैसला लिख लिया था। उनका आखिरी मैच वर्ल्ड कप फाइनल था, जिसमें अर्जेंटीना को स्पेन से हार मिली थी। मेसी ने लिखा कि उनके पिता जॉर्ज मेसी की मौत के बाद उन्हें लगा कि अर्जेंटीना के लिए करियर खत्म करने का यही सही समय है। जॉर्ज मेसी का 8 अगस्त को सेंट्रल अर्जेंटीना के रोसारियो शहर के एक अस्पताल में निधन हुआ था। वे 68 साल के थे।

पिता के निधन के बाद कहा था- ज्यादा नहीं खेल पाऊंगा

मेसी ने अपने पिता की मौत के बाद एक पोस्ट में लिखा था कि उन्हें इस बात को लेकर 'काफी संदेह' था कि वे ज्यादासमय तक अर्जेंटीना के लिए खेल पाएंगे या नहीं।उन्होंने स्पेन के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में अपने प्रदर्शन को लेकर भी लिखा था, 'मेरे पैर अब आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इस बार मैंने अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे जाने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका।'

स्टोक्स की 11 साल बाद बिग बैश लीग में वापसी

एडिलेड स्ट्राइकर्स से जुड़े. पूरा सीजन खेलेंगे

लंदन (एजेंसी)। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद बेन स्टोक्स बिग बैश लीग की टीम एडिलेड स्ट्राइकर्स से जुड़े हैं। वे फ्रेंचाइजी के साथ 5 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में जुड़े। एग्रीमेंट के अनुसार, अगर स्ट्राइकर्स क्वालिफाई करते हैं, तो स्टोक्स टूर्नामेंट के आखिरी दौर तक टीम के साथ रहेंगे। इस सीजन का फाइनल 26 जनवरी 2027 को होगा। स्टोक्स ने आखिरी बार 2015 की शुरुआत में बीबीएल मैच खेला था। 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल खेलने के बाद से उन्होंने कोई टी-20 क्रिकेट नहीं खेला है। बीबीएल ने इस पोस्ट के लिए स्टोक्स की वापसी का ऐलान किया।

स्टोक्स ने खुद स्ट्राइकर्स को चुना

स्टोक्स ने बीबीएल में लौटने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद साउथ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन (एसएसीए) के क्रिकेट जनरल मैनेजर साइमन इंस्ली ने उनसे बातचीत की। स्टोक्स को सिडनी सिक्सर्स और मेलबर्न रेनेगेड्स जैसी टीमों भी अपने साथ जोड़ना चाहती थीं। स्ट्राइकर्स अभी दो अन्य बड़े नामों के साथ बातचीत कर रहे हैं। टीम को उम्मीद है कि जल्द ही उनके साथ जुड़ने की पुष्टि कर दी जाएगी। उनका पहला मैच कैनबरा में सिडनी थंडर के खिलाफ होगा।

भारत ने पांच बार की फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील से खेलने के लिए टीम का किया ऐलान

कोलकाता (एजेंसी)। भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फीफा वर्ल्ड कप में भाग ले चुकी तीन टीमें-पनामा, ब्राजील और उरुग्वे- भारत का दौरा करने वाली है। ये तीनों टीमें सितंबर और अक्टूबर में भारतीय फुटबल टीम से फ्रेंडली मैच भी खेलने वाली है. जिससे भारत को खुद को परखने का मौका मिलेगा। भारतीय टीम 26 सितंबर को बेंगलुरु के श्री कांतीरवा स्टेडियम में पनामा के खिलाफ मैच खेलेगी. इसके बाद वे कोलकाता जाएंगे, जहां उनका मुकाबला 3 अक्टूबर को पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील और 6 अक्टूबर को दो बार की वर्ल्ड चैंपियन उरुग्वे से होगा। बता दें कि ये तीनों टीमें इस साल की शुरुआत में हुए स्वढ्न्न वर्ल्ड कप में खेली थीं, लेकिन पनामा और उरुग्वे ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थीं जबकि ब्राजील राउंड ऑफ 16 में नार्वे से हारकर बाहर हो गई थी। इस तीन इंटरनेशनल फ्रेंडली मैचों के लिए भारतीय फुटबॉल टीम के हेड कोच खालिद जमील ने 26 खिलाड़ियों की टीम की घोषणा भी कर दी. जिसमें चार गोलकीपर, आठ डिफेंडर, आठ मिडफील्डर और छह फॉरवर्ड शामिल हैं।

भारतीय फुटबॉल टीम

गोलकीपर- एल्बिनो गोम्स, गुरप्रीत सिंह संधू, प्रभसुखन सिंह गिल, सोम कुमार.
डिफेंडर- अभिषेक सिंह टेकचम, आकाश मिश्रा, अनवर अली, बिजॉय वर्गीज, ह्मिंगथनमाविया राल्टे, जय गुप्ता, प्रमवीर, रिकी मीतेई हाओबाम.
मिडफील्डर- अनिरुद्ध थापा, आशिक कुरुनियन, फारुख चौधरी, लालेंगमाविया राल्टे, मैकार्टन निक्सन, मोहम्मद सनन, रिकी शबोंग, सहल अब्दुल समद.
फॉरवर्ड- एडमंड लालरिंडिका, इरफान यादवाड, मनवीर सिंह, रहीम अली, रयान विलियम्स, विक्रम प्रताप सिंह।

चार रिजर्व खिलाड़ी

गोलकीपर ऋतिक तिवारी, डिफेंडर चिंगलेनसाना सिंह कोंशम और रोशन सिंह नाओरेम, मिडफील्डर सुरेश सिंह वांगजाम। पनामा के खिलाफ मैच से पहले तैयारी कैंप के लिए भारतीय टीम 14 सितंबर को बेंगलुरु में इकट्ठा होगी. पहला मैच खेलने के बाद, भारतीय टीम 28 सितंबर को कोलकाता के लिए रवाना होगी, ताकि विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में होने वाले बाकी दो मैचों की तैयारी कर सके।

फ्रेंडली मैच का कार्यक्रम

26 सितंबर - भारत बनाम पनामा - श्री कांतीरवा स्टेडियम, बेंगलुरु

3 अक्टूबर - भारत बनाम ब्राजील-विवेकानंद युवा भारती क्रीरांगन, कोलकाता

6 अक्टूबर - भारत बनाम उरुग्वे - विवेकानन्द युवा भारती क्रीरांगन, कोलकाता

वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में तीन रेसलर्स पर हमला

● उसोज और सिकोआ घायल,खून से सने विजुअल्स को ब्लर किए गए

नईदिल्ली (एजेंसी)। डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के हालिया एपिसोड में द उसोज, जिमी उसो और सोलो सिकोआ पर जानलेवा हमला किया गया। इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। शो के कमेंटेटर जो टेसिटोर ने इसकी जानकारी दी। हमले के वीडियो में इतना खून-खराबा था कि टीवी स्क्रीन पर विजुअल्स को ब्लर किया गया। फुटेज को फ्रीज करके सेंसर भी करना पड़ा।

द उसोज पर कार के पास हमला- रॉयस कीज और ओटीएम ने रॉ की शुरुआत में द उसोज, जिमी उसो पर हमला कर दिया।हमलावरों ने जिमी को कार के ऊपर पटक दिया। इसके बाद जे उसो को भी बुरी तरह पीटा गया। जे का चेहरा खून से लथपथ नजर आया, जिसके कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टीवी पर उस हिस्से को ब्लर कर दिया।

हमले के दौरान जैकब फाटू वहां पहुंचे और हमलावरों का पीछा करने की कोशिश की। हालांकि, रॉयस कीज और ओटीएम वहां से निकल गए। इस हमले ने रॉयस कीज और ओटीएम को डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक बड़े खतरे के तौर पर स्थापित कर दिया है।

सोलो सिकोआ पर बैकस्टेज हमला

सोलो सिकोआ को बैकस्टेज निशाना बनाया गया। इसके बाद वह घायल हालत में पड़े मिले। इस हमले के लिए रोमन रेंस का नाम सामने आया, लेकिन रेंस ने इसमें अपना हाथ होने से इनकार किया। रेंस ने एलए नाइट का नाम भी इस मामले में नहीं जोड़ने की बात कही।

तीनों को मेडिकल सेंटर ले जाया गया

जो टेसिटोर ने बताया कि रॉ में हुई घटना के बाद कई स्टार्स को अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने कहा कि सोलो सिकोआ, जे उसो और जिमी उसो को स्थानीय मेडिकल सेंटर पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर इन तीनों की चोटों का आकलन कर रहे हैं। जो टेसिटोर ने कहा,हमें अभी इस बात की जानकारी मिली है, जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं।

मुझे हमेशा याद रहेगा... आईसीसी चेयरमैन जय शाह का लियोनेल मेसी के रिटायरमेंट पर बड़ा बयान

अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने 31 अगस्त को इंटरनेशनल फुटबॉल को अलविदा कह दिया. जिसके बाद खेल से जुड़ी बड़ी से बड़ी हस्तियां उन्हें शानदार करियर के लिए बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी क्रम में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के चेयरमैन जय शाह ने मंगलवार को मेसी से मुलाकात को याद करते हुए उनके इंटरनेशनल करियर के लिए बधाई दी और अगले सफर के लिए शुभकामनाएं भी दीं। जय शाह ने एक्स पर एक तस्वीर शेयर करके लिखा, एक यादगार इंटरनेशनल सफर का अब समाप्त हो रहा है. भारत की आपकी ऐतिहासिक यात्रा के दौरान हुई हमारी मुलाकात को याद करते हुए, मैदान पर आपकी बेमिसाल प्रतिभा के साथ-साथ आपका जबरदस्त विनम्र स्वभाव भी मुझे हमेशा याद रहेगा. आपको व्यक्तिगत रूप से हमारे देश की जर्सी भेंट करना, खेल जगत के लिए एक गर्व भरा पल था।

लाबुशेन ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम से बाहर

- जिम्बाब्वे-साउथ अफीका सीरीज के लिए नहीं चुने गए
- जोएल डेविस को मौका, स्टार्क-कमिंस की वापसी

सिडनी (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका दौरे के लिए 17 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। खराब फॉर्म से जूझ रहे मार्नस लाबुशेन को टीम में जगह नहीं मिली है। वहीं जोएल डेविस पहली बार वनडे टीम में चुने गए हैं। मिचेल मार्श और ट्रैविस हेड की वापसी हुई है, जबकि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम से जुड़ेंगे।

लाबुशेन ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में अर्धशतक लगाया - लाबुशेन लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत के खिलाफ नाबाद अर्धशतक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

राष्ट्रपति से भेंट कर लौटे प्रतिभावान विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से की सौजन्य मुलाकात

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विद्यार्थियों को दी बधाई, कहा- आपकी उपलब्धि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय

एक सत बुलेटिन, रायपुर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से भेंट कर लौटे छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने सौजन्य मुलाकात की। विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री श्री साय को राष्ट्रपति भवन की अपनी यादगार यात्रा और राष्ट्रपति महोदया के साथ हुए आत्मीय संवाद के अनुभव सुनाए। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को इस विशेष अवसर के लिए बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करना अपने आप में गौरव की बात है। प्रदेश के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक प्रस्तुति से छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद करते हुए उनकी यात्रा के संबंध में जानकारी ली। विद्यार्थियों ने बताया कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मिलना उनके जीवन का अविस्मरणीय अनुभव रहा। राष्ट्रपति महोदया ने उनसे सहजता और आत्मीयता के साथ बातचीत की तथा उनकी शिक्षा, रुचियों और

भविष्य की आकांक्षाओं के बारे में जाना। विद्यार्थियों ने राष्ट्रपति भवन के भ्रमण और वहां बिताए क्षणों से जुड़े अपने अनुभव भी मुख्यमंत्री के साथ साझा किए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे बच्चों में प्रतिभा और संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। उन्हें सही अवसर, प्रोत्साहन और मंच मिले तो वे हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर सकते हैं। ऐसे अवसर विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ उनके सपनों को नई ऊंचाई देते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से पूरी लगन और मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखने तथा जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। उल्लेखनीय है कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से भेंट और संवाद का विशेष अवसर प्राप्त हुआ था। इस अवसर पर राष्ट्रपति महोदया ने विद्यार्थियों से आत्मीयतापूर्वक बातचीत की। उन्होंने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। राष्ट्रपति भवन में इस मुलाकात का एक

अत्यंत भावुक और यादगार क्षण उस समय आया, जब राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने विद्यार्थी नुकेश कुमार वर्मा को स्वयं राखी बांधी। राष्ट्रपति महोदया का यह आत्मीय स्नेह नुकेश के साथ ही वहां उपस्थित विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए भी जीवनभर संजोकर रखने वाली स्मृति बन गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति की सुंदर झलक भी राष्ट्रपति भवन में देखने को मिली। छात्राओं ने प्रदेश के पारंपरिक सुवा नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी। छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा, गीत-संगीत और सांस्कृतिक सौंदर्य से सजी इस प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने प्रस्तुति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह विशेष रूप से प्रसन्नता की बात है कि प्रदेश के बच्चों ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा से जुड़े राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ की प्रतिभा के साथ उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी सुंदर परिचय दिया। उन्होंने कहा कि हमारी लोक संस्कृति हमारी पहचान और हमारी अमूल्य धरोहर है। नई पीढ़ी जब इसे आत्मसात कर देश के प्रतिष्ठित मंचों पर प्रस्तुत करती है, तो हमारी परंपराओं को नई ऊर्जा और व्यापक पहचान मिलती है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि राष्ट्रपति महोदया से प्राप्त प्रोत्साहन और इस यात्रा से मिले अनुभव को वे अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा बनाएं। उन्होंने सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वे अपने सपनों को बड़ा रखें, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और अपनी उपलब्धियों से परिवार, प्रदेश और देश को गौरवान्वित करें। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से भेंट करने वाले विद्यार्थियों में नारायणपुर जिले की राजवती पोयाम, सुकमा जिले के हिमांशु ठाकुर, दुर्ग जिले की पायल राजानी, महासमुंद जिले की रागनी साहू, रायपुर जिले के नुकेश कुमार वर्मा तथा महासमुंद जिले के दुर्गेश साहू एवं डिगेश सेन शामिल थे। इस अवसर पर डॉ. मुक्ति बैस, राज्य नोडल अधिकारी, समग्र शिक्षा, रायपुर तथा श्री चंद्रशेखर मिथलेश, व्याख्याता (भौतिकी), शासकीय आशी बाई गोलछा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महासमुंद भी उपस्थित थे।

वर्तमान पर फोकस करें, निरंतर सीखते रहें और समाज के लिए योगदान दें : राज्यपाल डेका

एक सत बुलेटिन, रायपुर

संत गोबिंदराम शदाणी शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, रायपुर में वर्ष 2026-27 में नवप्रवेशित छात्राओं का दीक्षारंभ कार्यक्रम आज राज्यपाल श्री रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्रतिभाशाली छात्राओं का राज्यपाल ने सम्मान भी किया। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने नवप्रवेशित छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह अध्याय उन्हें केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि एक जागरूक, सशक्त और संवेदनशील नागरिक के रूप में तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि इस महाविद्यालय में कदम रखते ही छात्राएं उस गौरवशाली परंपरा की उत्तराधिकारी बन गई हैं, जिसने दशकों से बालिकाओं को ज्ञान और शिक्षा का प्रकाश प्रदान किया है। श्री डेका ने महिलाओं की तुलना पानी से करते हुए कहा कि जिस प्रकार पानी के बिना जीवन अधूरा है, उसी प्रकार महिलाओं के बिना समाज भी अधूरा है। उन्होंने छात्राओं से कहा कि वे अपने पास जो कुछ है, उससे संतुष्ट रहें, लेकिन अपने भविष्य को लेकर निरंतर प्रयास करती रहें। जीवन में आगे बढ़ने के अनेक अवसर और क्षेत्र हैं। यदि किसी एक क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है तो निराश होने के बजाय अन्य अवसरों का लाभ उठाकर कर आगे बढ़ना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि जीवन सतत सीखने की प्रक्रिया है और हम जीवनभर विद्यार्थी बने रहते हैं। उन्होंने छात्राओं से कहा कि आप इंटरनेट युग के विद्यार्थी हैं, तकनीक ने ज्ञान के नए द्वार खोले हैं, लेकिन तकनीक पर पूर्ण निर्भरता उचित नहीं है। इंटरनेट से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन यह मानव बुद्धि और विवेक का स्थान नहीं ले सकता। जीवन को सरल, सार्थक और बेहतर बनाने के लिए ज्ञान प्राप्त करना तथा उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमें केवल यह नहीं सोचना चाहिए कि समाज ने हमें क्या दिया, बल्कि यह भी विचार करना चाहिए कि हम समाज, अपने पड़ोस और देश की बेहतरी के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। जीवन अनमोल है, इसलिए इसे अनावश्यक चिंताओं में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हुए कठोर परिश्रम करना चाहिए। निरंतर प्रयासों से भविष्य निश्चित रूप से बेहतर बनेगा।

धमतरी में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान

रायपुर। स्वर्गीय छोटेलाल श्रीवास्तव स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से बचाने और कुपोषण-मुक्त स्वस्थ भारत के निर्माण का संदेश देने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो, रायपुर द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान' और 'राष्ट्रीय पोषण माह' को समर्पित रहा, जिसमें कॉलेज के युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और स्वस्थ तथा जिम्मेदार जीवन जीने का संकल्प उठाया। युवाओं को सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर अपनी ऊर्जा, क्षमता और प्रतिभा का उपयोग शिक्षा, खेल, नवाचार और राष्ट्र निर्माण में करना चाहिए कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष ने ज्ञानवर्धक चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन कर किया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि युवावस्था जीवन की दिशा तय करने का सबसे स्वर्णिम पड़ाव है। युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर अपनी ऊर्जा, क्षमता और प्रतिभा का उपयोग शिक्षा, खेल, नवाचार और राष्ट्र निर्माण में करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति के शरीर को ही नहीं तोड़ता, बल्कि उसके परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी अंधकार में धकेल देता है। वर्ष 2047 के विकसित भारत का सपना तभी सच होगा जब देश की युवा शक्ति स्वस्थ, अनुशासित और जागरूक होगी।

4500 से अधिक हितग्राहियों को मिलेगा लाभ

जामबहार में बनेगा 3.40 करोड़ की लागत से नया सबस्टेशन

एक सत बुलेटिन, रायपुर

छत्तीसगढ़ के उद्योग, वाणिज्य, श्रम व आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा जिले के बालको क्षेत्र से लगे ग्राम पंचायत जामबहार में 3.40 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 33/11 के.वी. (05 एम.वी.ए. क्षमता) विद्युत सबस्टेशन का विधिवत भूमिपूजन किया। इस नए सबस्टेशन के निर्माण से क्षेत्र की बिजली आपूर्ति में गुणवत्ता आएगी और आसपास के अन्य सबस्टेशनों पर दबाव कम होगा। शहरी व ग्रामीण बस्तियों में सुधरेगी बिजली आपूर्ति सबस्टेशन निर्माण के लाभ रेखांकित करते हुए उद्योग मंत्री देवांगन ने बताया कि इससे कोरबा शहरी क्षेत्र के रूमगरा, बेलगिरी बस्ती, मदरसा मोहल्ला, हवाई पट्टी, खान मोहल्ला और जोगियाडेरा जैसी बस्तियों को बेहतर बिजली मिलेगी। वहीं, ग्रामीण क्षेत्र के जामबहार, रोकबहरी, सोनपुरी, परसाबातेल और चुहिया में भी सुचारू विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित होगी। योजना से 4,500 से अधिक उपभोक्ता सीधे लाभान्वित होंगे। सौर ऊर्जा और योजनाओं का

लाभ उठाने की अपील समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा हर घर तक समुचित बिजली पहुंचाना है। उन्होंने ग्रामीणों से 'प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना' और 'बिजली बिल समाधान योजना' का लाभ उठाने की अपील की। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह और जिला पंचायत सदस्य रेणुका राठिया ने मंत्री के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण कदम बताया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि रफीक मेमन, निगम पार्षद नरेंद्र देवांगन, सीमा कंवर, जामबहार सरपंच उपन सिंह कंवर तथा बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालन अभियंता सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

सैनिक स्कूल विद्यार्थियों में अनुशासन और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करने में निभाते हैं भूमिका : अग्रवाल

एक सत बुलेटिन, रायपुर

सैनिक स्कूल अंबिकापुर का 18वां स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास, उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में विद्यालय की 18 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, उपलब्धियों तथा कैडेटों की प्रतिभा को विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। सैनिक स्कूल अंबिकापुर का 18वां स्थापना दिवस समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न समारोह के मुख्य अतिथि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल रहे। इस अवसर पर सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री दीपक कुमार झा, कलेक्टर श्री अजीत वसंत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुमार अग्रवाल सहित संभाग एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के आगमन पर गार्ड ऑफ ऑनर से हुआ। अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया

गया। इसके पश्चात दीप प्रज्ज्वलन के साथ समारोह का विधिवत शुभारंभ हुआ। विद्यालय की 18 वर्षों की गौरवशाली यात्रा के उपलक्ष्य में अतिथियों ने केक काटकर स्थापना दिवस मनाया। विद्यालय के प्राचार्य कर्नल राजेश बैंदा ने सत्र 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों, खेलकूद गतिविधियों, सह-पाठ्यक्रम कार्यक्रमों तथा कैडेटों के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन की जानकारी दी।

जिला मुख्यालय पर अपर कलेक्टर ने की जनसुनवाई, 65 प्रकरणों की हुई सुनवाई

भिण्ड। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई जनसुनवाई में अपर कलेक्टर श्री एल.के. पाण्डेय ने जिले के विभिन्न अंचलों से अपनी समस्याओं का आवेदन लेकर आये 65 आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण करने के संबंध में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान अपर कलेक्टर ने गंभीर बीमारी से संबंधित इलाज, विद्युत बिलों में सुधार, हैण्डपंपों का संधारण, पेंशन, सड़क दुर्घटना सहायता, हितग्राही मूलक योजनाओं, बीपीएल राशन कार्ड एवं जमीन पर कब्जा से संबंधित आवेदनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके संबंध में आवेदक को भी कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश भी दिए।

तीन दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन का शुभारंभ, मुक्ताकाशी मंच पर लोकवाद्य, तबला, बांसुरी, पियानो और लोकगायन की मनमोहक प्रस्तुतियां

'रंग-तरंग' में गूंजे छत्तीसगढ़ के लोकवाद्य, लोकधुनों से सुरों तक दिखा संस्कृति का रंग

एक सत बुलेटिन, रायपुर

छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकसंगीत परंपरा, पारंपरिक वाद्ययंत्रों और आधुनिक संगीत के सुरों को एक मंच पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आयोजित तीन दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन 'रंग-तरंग' का मंगलवार को महंत घासीदास संग्रहालय परिसर स्थित मुक्ताकाशी मंच पर शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में लोकवाद्यों की गूंज, शास्त्रीय वाद्ययंत्रों की मधुर धुनों और लोकगायन की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया। 'रंग-तरंग' में गूंजे छत्तीसगढ़ के लोकवाद्य, लोकधुनों से आधुनिक सुरों तक दिखा संस्कृति का रंग 'रंग-तरंग' का आयोजन 1 से 3 सितंबर 2026 तक प्रतिदिन शाम 7 बजे से किया जा रहा है। आयोजन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की लोक एवं वाद्य संगीत परंपरा को संरक्षित करने, नई पीढ़ी तक पहुंचाने तथा लोक एवं वाद्य संगीत से जुड़े कलाकारों को बेहतर मंच उपलब्ध कराना है। आयोजन के शुभारंभ अवसर पर विभिन्न वाद्य एवं संगीत प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोक वादन (फ्यूजन) की प्रस्तुति श्री विवेकानंद भारती एवं साथियों ने दी। पियानो वादन में मोहम्मद अयान रायकर, तबला वादन में नासिर खान, अंबिकापुर, बांसुरी वादन में

श्री तारकेश्वर वर्मा, रायपुर तथा लोक गायन में राहुल ठाकुर, रायपुर ने अपनी प्रस्तुतियों से सुरों की मनमोहक छटा बिखेरी। लोकधुनों और पारंपरिक वाद्यों के साथ आधुनिक संगीत के सुरों का संगम कार्यक्रम की खासियत रहा। प्रस्तुतियों में छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति की सहजता और विविधता के साथ संगीत के नए प्रयोगों की झलक भी देखने को मिली। परंपरा और आधुनिकता का संगम जरूरी : डॉ. संजय कन्नौजे संस्कृति एवं पुरातत्व संचालक डॉ. संजय कन्नौजे ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध लोकसंस्कृति और संगीत परंपरा से है। यहां के पारंपरिक वाद्ययंत्र केवल संगीत के साधन नहीं हैं, बल्कि वे हमारी सांस्कृतिक पहचान और लोकजीवन की जीवंत अभिव्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि 'रंग-तरंग' के माध्यम से पारंपरिक लोकवाद्यों और लोकधुनों को आधुनिक संगीत के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के साथ ही कलाकारों को व्यापक पहचान दिलाने में मदद मिलेगी। डॉ. कन्नौजे ने कहा कि वाद्य एवं संगीत कलाकारों के लिए ऐसे मंच उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर मिलने से कलाकारों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें व्यापक स्तर पर प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। विभाग का प्रयास है कि छत्तीसगढ़ की लोक एवं वाद्य संगीत परंपरा से जुड़े कलाकारों को निरंतर प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें नए मंच उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में परंपरा को आधुनिकता से जोड़ना आवश्यक है।

8 सितंबर से नामांकन, 15 सितंबर तक आवेदन, 3 अक्टूबर को आ जाएंगे अधिकांश नतीजे

मध्यप्रदेश में बज गया चुनावी बिगुल, नगरीय निकाय और पंचायत उपचुनाव 29 सितंबर को

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 29 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया 8 सितंबर से शुरू होगी। आयोग ने सोमवार को उपचुनाव का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दिनेश श्रीवास्तव के मुताबिक 8 सितंबर को उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन पत्र जमा होने शुरू हो जाएंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। 16 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि उम्मीदवार 18 सितंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। इसी दिन चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। नगरीय निकायों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। पंचायतों के लिए मतदान का समय सुबह से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। इतने पदों पर

होगा चुनाव पंचायत उपचुनाव के तहत जिला पंचायत के 7, जनपद पंचायत के 28 और सरपंच के 110 पदों के लिए मतदान होगा। इसके अलावा 4,090 पंच पदों पर भी चुनाव कराया जाएगा। नगरीय निकायों में नगर परिषद सुसनेर, नगर पालिका टीकमगढ़ और नगर परिषद कुक्षी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। इसके साथ ही अलग-अलग नगरीय निकायों में 26 पार्षद पदों के लिए भी मतदान कराया जाएगा। इनमें इंदौर नगर निगम के वार्ड 58 और 60, ग्वालियर नगर निगम का वार्ड 5 तथा सागर नगर निगम का वार्ड 11 सहित अन्य रिक्त वार्ड शामिल हैं। 3 और 5 अक्टूबर को आएंगे परिणाम पंच पद के लिए मतगणना मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद संबंधित मतदान केंद्र पर ही की जाएगी। सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतगणना होगी। सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य के चुनाव की मतगणना 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से होगी और इसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। सदस्यों के परिणाम 5 अक्टूबर को घोषित होंगे। इस तरह उपचुनाव के साथ प्रदेश में स्थानीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होने की संभावना है।

परिणाम 3 और 5 अक्टूबर को जारी होंगे

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के रिक्त पड़े नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों में उपचुनाव का शंखनाद कर दिया गया है। घोषित शेड्यूल के अनुसार, प्रदेश भर में 29 सितंबर 2026 को मतदान कराया जाएगा, जिसके बाद परिणाम 3 और 5 अक्टूबर को जारी होंगे। श्धङ्करूसे होगा मतदान, 8 सितंबर से शुरू होगी नामांकन प्रक्रियानिर्वाचन आयोग की अधिसूचना के तहत चुनाव की प्रक्रिया 8 सितंबर को आधिकारिक घोषणा के साथ शुरू होगी। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर तय की गई है, जबकि नाम वापसी और चुनाव चिन्हों का आवंटन 18 सितंबर को होगा। इस बार पंचायत उपचुनावों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्य चुनावी बिंदु और पदःनगर निगम व परिषदः सुसनेर टीकमगढ़ और कुक्षी (धार) में अध्यक्ष पद समेत इंदौर, ग्वालियर, सागर व कटनी जैसे प्रमुख शहरों के 26 पार्षद पदों पर उपचुनाव होंगे। त्रिस्तरीय पंचायतः 7 जिला पंचायत सदस्य, 28 जनपद पंचायत सदस्य, 110 सरपंच और 4,090 पंच पदों पर मतदान कराया जाएगा। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक और पंचायतों में दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा।

छात्रावासों में शीघ्र प्रारंभ होगा मेस संचालनः राज्यमंत्री कृष्णा गौर

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने मंगलवार को मंत्रालय में विभागीय योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में विद्यार्थियों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने निर्देश दिए कि पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिये संचालित 106 छात्रावासों में आगामी 8 सितंबर से मेस का संचालन अनिवार्य रूप से प्रारंभ किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को पौष्टिक एवं उच्च गुणवत्तायुक्त भोजन समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजनाः वर्षभर खुला रहेगा पोर्टल, त्रैमासिक होंगे साक्षात्कार उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के इच्छुक प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने 'विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना' के पोर्टल को पूरे वर्ष संचालित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवेदन प्रक्रिया को सुगम और निरंतर बनाए रखने के लिए पोर्टल बंद नहीं होना चाहिए। चयन प्रक्रिया को तीव्र गति देने के उद्देश्य से उन्होंने व्यवस्था बनाई कि प्रत्येक तीन माह (त्रैमासिक) में अथवा न्यूनतम 25 आवेदन प्राप्त होते ही समिति की बैठक आयोजित कर अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए जाएं, जिससे पात्र विद्यार्थियों को समय पर योजना का लाभ मिल सके।

सैन्य अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर सौंपे गए दायित्वों का समय-सीमा में करें निर्वहन : कलेक्टर

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

भोपाल में आगामी 15 जनवरी 2027 को आयोजित होने वाली ऐतिहासिक 'सेना दिवस परेड' की तैयारियों के दृष्टिगत मंगलवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय के सभाकक्ष में विभागीय बैठक की गई। कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा ने कहा कि यह भव्य आयोजन राजधानी भोपाल के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। अतः सभी संबंधित विभाग अपने-अपने सौंपे गए दायित्वों का पूर्ण जवाबदेही एवं उत्कृष्ट समन्वय के साथ निर्धारित समयावधि में निर्वहन सुनिश्चित करें। उन्होंने भारतीय सेना के कर्नल सनी जूनेजा एवं कर्नल श्री सुब्रत मिश्रा के साथ सतत संपर्क बनाए रखने पर बल दिया। सेना दिवस परेड के विशिष्ट मानकों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप सैन्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत

किए गए प्रस्तावों व दिशा-निर्देशों का सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ अनुपालन किया जाए, ताकि इस गरिमामयी समारोह को पूर्ण भव्यता और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संपन्न कराया जा सके। बैठक में कर्नल श्री सनी जुनेजा, कर्नल श्री सुब्रत मिश्रा,एडीएम श्री महेंद्र कवचे, एसडीएम श्री आशुतोष शर्मा, श्रीमती निधि चौकसे, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश विद्युत विभाग, नगर पालिक निगम भोपाल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, राजधानी परियोजना प्रशासन सहित विभिन्न सम्बद्ध विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्य में लापरवाही बरतने पर सहायक श्रम पदाधिकारी को कारण बताओ नोटिस

भोपाल। संभाग आयुक्त श्री कर्मवीर शर्मा ने मंडीदीप, रायसेन के सहायक श्रम पदाधिकारी श्री हरदीप सिंह सैनी को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।च संभागायुक्त भोपाल की अध्यक्षता में गत दिवस सम्पन्न श्रम विभाग की समीक्षा बैठक में श्री हरदीप सिंह सैनी सहायक श्रमपदाधिकारी, मण्डीदीप जिला रायसेन बंधक श्रमिक प्रकरणों की पूर्ण एवं तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत नहीं कर पाए। साथ ही विभागीय समीक्षा में मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल संबल योजना अंतर्गत पंजीयन हेतु संभाग अंतर्गत सर्वाधिक आवेदन रायसेन जिले के लंबित पाये गए. इस पर संभागायुक्त द्वारा श्री सैनी को कारण बताओ सूचना- पत्र जारी किया गया है।

दिव्यांगता को नहीं बनने दिया बाधा, आत्मनिर्भरता की मिसाल बने अंकित सक्सेना, बैंकिंग का कर रहे प्रबंधन

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

जन्मजात सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित रायसेन के अंकित सक्सेना ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति, परिवार के सहयोग और विशेषज्ञ चिकित्सकीय सहायता के बल पर आत्मनिर्भरता की प्रेरक मिसाल प्रस्तुत की है। शारीरिक चुनौतियों के बावजूद अंकित आज न केवल अपने पिता के साथ व्यवसाय संभाल रहे हैं, बल्कि डिजिटल एवं वित्तीय प्रबंधन में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अंकित ने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद फिटर ट्रेड से आईटीआई की शिक्षा पूर्ण की। उनकी शैक्षणिक उपलब्धि सीखने की लगन और तकनीकी विषयों के प्रति उनकी समझ को प्रदर्शित करती है। अंकित के जीवन में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र रायसेन की सेवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्र की ईयर मोल्ड टेक्नीशियन श्रीमती आरती पटेल तथा फिजियोथेरेपिस्ट श्रीमती आभा गुप्ता द्वारा उन्हें नियमित रूप से एक-एक घंटे के थेरेपी सत्र दिए गए। स्पीच थेरेपी से उनकी वाणी और शब्दों के उच्चारण में स्पष्टता आई, वहीं नियमित फिजियोथेरेपी से उनकी शारीरिक गतिशीलता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। निरंतर अभ्यास और उपचार के परिणामस्वरूप अंकित अब स्वतंत्र रूप से चलने के साथ स्कूटी तथा मैजिक चार-पहिया वाहन भी चलाने में सक्षम हैं। वे कृषि उपज मंडी रायसेन में अपने पिता के साथ व्यापार संभालते हैं। अनाज की तौल, भाव निर्धारित करने और नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने जैसे कार्य वे पूरी दक्षता से कर रहे हैं। अंकित तकनीक के उपयोग में भी पारंगत हैं। वे लैपटॉप पर व्यवसाय का प्रतिदिन का आय-व्यय और लेखा-जोखा रखते हैं तथा बैंक संबंधी लेनदेन का प्रबंधन भी स्वयं करते हैं। शासकीय सेवा में जाने के लक्ष्य के साथ वे वन विभाग में दिव्यांगजन के लिए आरक्षित सहायक वर्ग-3 के पद की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं। अंकित की सक्रियता और आत्मविश्वास को देखते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय ने विधानसभा निर्वाचन-2023 के दौरान उन्हें रायसेन जिले के 'दिव्यांग आइकॉन' के रूप में चयनित किया था। अन्य दिव्यांगजनों को भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया।

विधानसभा निर्वाचन-2023 में रायसेन जिले के दिव्यांग आइकॉन के रूप में हुए थे चयनित

'हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी' की थीम पर मनेगा 9वां राष्ट्रीय पोषण माह

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

इस वर्ष 9वें राष्ट्रीय पोषण माह-2026 का आयोजन 'हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी' की थीम पर व्यापक जनभागीदारी के साथ किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत आयोजित होने वाले पोषण माह का उद्देश्य आंगनवाड़ी केन्द्रों को पोषण, देखभाल और प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास की गतिविधियों का प्रभावी केन्द्र बनाते हुए समुदाय की सक्रिय भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

इस वर्ष 9 सितम्बर से राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। पोषण को जनआंदोलन बनाने पर जोर इस वर्ष पोषण माह को केवल जागरूकता अभियान तक सीमित न रखते हुए समुदाय को आंगनवाड़ी केन्द्रों से जोड़ने और पोषण सेवाओं में उसकी भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके लिए प्रदेशभर में स्थानीय खाद्य पदार्थों, संतुलित आहार, पर्याप्त प्रोटीन, बच्चों के प्रारंभिक विकास, गर्म पके भोजन की गुणवत्ता तथा मातृ स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियां आयोजित होंगी। स्थानीय खाद्य पदार्थों से सजेगा पोषण का संदेश आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन को लेकर आंगनवाड़ी केन्द्रों पर स्थानीय एवं कम लागत में उपलब्ध खाद्य पदार्थों से पौष्टिक व्यंजनों की रेसिपी डेमोंस्ट्रेशन गतिविधियां होंगी। पोषण मेलों के माध्यम से स्थानीय सुपर फूड, मौसमी फल-सब्जियों, दालों, अनाज, मिलेट्स, दूध एवं दुग्ध उत्पाद, मेवा और बीज सहित प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थों की उपयोगिता बताई जाएगी। 'प्रोटीन रिच फूड' अभियान के माध्यम से परिवारों को रोजमर्रा के भोजन में किफायती और आसानी से उपलब्ध प्रोटीन स्रोत शामिल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। खाद्य पदार्थों तथा स्थानीय मौसमी खाद्य सामग्री को भी प्रदर्शित कर उनके नियमित उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

भोपाल में ई-कचरा बना जहरीला खतरा, खुले में जलाए जा रहे मोबाइल-कंप्यूटर से सीसा, एनजीटी ने मांगी जांच रिपोर्ट

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

भोपाल में बढ़ते ई-कचरे के निस्तारण को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। शहर में मोबाइल, कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कचरे को कथित तौर पर खुले में जलाने और अनधिकृत इकाइयों में असुरक्षित तरीके से तोडने़-प्रसंस्करण करने के आरोपों की अब जांच होगी। अधिकरण ने पर्यावरण और जनस्वास्थ्य पर पडने़ वाले संभावित असर की तथ्यात्मक जांच के लिए समिति गठित कर चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। मामले की सुनवाई सोमवार को न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ के समक्ष हुई। नितिन सक्सेना की ओर से दायर आवेदन में भोपाल में ई-कचरे के कथित अनुचित निस्तारण, प्रसंस्करण और खुले में जलाने से जुड़े गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं। अधिकरण के सामने रखी गई सामग्री में दावा किया गया है कि भोपाल में पैदा होने वाले ई-कचरे के सीमित हिस्से का ही वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण हो रहा है। बाकी कचरे के अनधिकृत कबाड़ इकाइयों के जरिए असुरक्षित तरीके से प्रसंस्करण किए जाने का आरोप है। पुराने मोबाइल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उनके पुर्जो को तोडने़ या जलाने की प्रक्रिया अगर खुले में होती है तो इससे पर्यावरण में जहरीले तत्व पहुंचने का खतरा बढ़ सकता है। एनजीटी के आदेश में दर्ज आरोपों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खुले में जलाने या नष्ट करने से सीसा, पारा, कैडमियम और क्रोमियम जैसी भारी धातुएं निकल सकती हैं। इनके कारण हवा, पानी और मिट्टी के प्रदूषित होने की आशंका है। इसका असर मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। आवेदन में मध्य प्रदेश में ई-कचरे की मात्रा तेजी से बढने़ का भी उल्लेख किया गया है। इसमें दावा किया गया है कि राज्य में हर साल करीब 5 हजार मीट्रिक टन ई-कचरा निकल रहा है।

ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक निर्धारित समय पर उपस्थित रहें: उप मुख्यमंत्री

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न विषयों की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने तथा आमजन को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक निर्धारित समय पर उपस्थित रहें, इसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निगरानी व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से लागू की जाएं। चिकित्सकों की उपस्थिति एवं कार्यप्रणाली की नियमित निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने विशेषज्ञ

चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में विभाग में अन्य रिक्त पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने आवश्यकतानुसार भर्ती प्रक्रिया को गति देने और मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

व्यापारियो ने किया उग्र प्रदर्शन, करोंद में भारी आक्रोश देख वापस लौटी टीम

सीलिंग कार्रवाई का राजधानी में चारो और विरोध जारी

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

राजधानी भोपाल के रहवासी इलाको में व्यावसायिक गतिविधियों पर नगर निगम द्वारा की जा रही सीलिंग कार्रवाई का राजधानी में चारो और विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को निगम कार्यवाही के दौरन ही व्यापारियों ने उग्र प्रदर्शन किया। भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले सैकड़ों कारोबारी न्यू मार्केट से सीएम आवास की ओर बढ़े, लेकिन रोशनपुरा चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान व्यापारियों और पुलिस के बीच विवाद की स्थिति भी बनी। गुस्साये ने निगम कार्यवाही के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर निम वापस जाओ और तानाशाही बंद करो जैसे नारे लगाए। साथ ही व्यापारियो ने सरकार को जगाने के लिए थाली, शंख तथा डमरू बजाए। मौके पर पहुंचे एसीपी अखिल पटेल ने व्यापारियों को समझाइश देते हुए शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन वे मुख्यमंत्री से मिलने की मांग पर अड़े रहे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपने से मना कर दिया। करीब

चार घंटे बाद एसडीएम अर्चना शर्मा के आश्वासन पर आंदोलन समाप्त हुआ। दूसरी ओर, विरोध प्रदर्शन के बीच नगर निगम ने कोहेफिजा इलाके में चाय लीला कैफे, बैकरी, होटल और बुक शॉप पर सीलिंग की कार्रवाई जारी रखी। करोंद इलाके में भी निगम अमले ने सागर गैरे, दरबार ए खास और टाटा मोटर्स को सील किया। इलाके में हो रही कार्यवाही की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में कारोबारी मौके पर पहुंच गये और निगम टीम के सामने ही नारेबाजी करते हुए विरोध पदर्शन किया। भारी विरोध को देखते हुए आगे की कार्यवाही न करते हुए टीम वापस लौट गई। भोपाल व्यापारी महासंघ संघर्ष समिति के अध्यक्ष आनंद सोनी और चैंबर अध्यक्ष गोविंद गोयल ने कहा कि प्रशासन की कार्रवाई से पूरे शहर का व्यापार ठप हो गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मांग की कि सीलिंग तुरंत रोककर नया मास्टर प्लान लागू किया जाए।

स्वामी **एक सत प्रयास जनकल्याण समिति** के लिए मुद्रक प्रकाशक एवं **सम्पादक अमित शर्मा** द्वारा 401, जीवन छाया अपार्टमेंट, राइट टाउन, जबलपुर (मप्र) पिन: 482004 से प्रकाशित एवं पीजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, रिछाई, जबलपुर, मध्य प्रदेश 482002 से मुद्रित। पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार।
RNI-MPHIN/2019/78787, स्थानीय संपादक: विक्रम सिंह। E-mail:eksatbulletin@gmail.com, मार्केटिंग एवं अन्य जानकारी हेतु हेड ऑफिस संपर्क करें- ए-1 माचना कॉलोनी, शा.राजीव गांधी हाई स्कूल शिवाजी नगर 6 नंबर बस स्टाप पास भोपाल। फोन: 0755-4515227, मोबाइल: 9893311784